RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

11 वर्ष

दैनिक सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, गुरुवार ●29 फरवरी , 2024 वर्षः-11 अंक - 302 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

महाकाल के दर पर दिखीं सीएम मोहन यादव की नई नवेली बहू

पति के साथ सामने आईं पूजा की तस्वीरें, हाल ही में संपन्न हुआ है विवाह

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुपुत्र का विवाह हाल ही में संपन्न हुआ। जो काफी सादगी भरा रहा और चर्चाओं का विषय बना रहा। विवाह संपन्न होने के पश्चात सर्वप्रथम अपने ईष्ट को शीश नवाने मुख्यमंत्री के सुपुत्र व पुत्रवधू आज बाबा महाकालेश्वर के दर पर पहुंचे। सीएम मोहन यादव के बेटे और बहू आशीर्वाद लेने श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और अपने ईष्ट का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सुपुत्र वैभव यादव और बहू शालिनी यादव ने दांपत्य जीवन

की शुरुआत बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ की। पूरा परिवार इस दौरान महाकाल की भक्ति में लीन दिखा। पूजा खत्म होने के बाद परिवार ने तस्वीरें क्लिक करवाईं। पूजा खत्म होने के बाद नवदंपति ने एक साथ मंदिर परिसर के बाहर तस्वीरें भी क्लिक करवाईं। दोनों ने भगवान से खुशहाल दांपत्य जीवन का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ यादव के छोटे पुत्र अभिमन्यु यादव, बहन कलावती यादव (अध्यक्ष नगर पालिक निगम) भी शामिल थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंदिर प्रशासक के निज सहायक प्रशान्त त्रिपाठी व प्रोटोकॉल सहायक चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया, बल्कि नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल से सफल दांपत्य जीवन के लिए मनोकामना भी मांगी।

हिमाचल में ड्रामा जारी, सीएम ने खुद को बताया योद्धा

- पुष्पा स्टाइल में बीजेपी को दिया जवाब, इस्तीफे से इंकार

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल में मचे सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। सीएम ने इस्तीफा देने की खबरों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम ने दावा किया है कि उनकी सरकारी पूरे पांच साल चलेगी। मैं एक योद्धा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। कुछ भाजपा विधायक हमारे संपर्क में हैं। हिमाचल में यह सब भाजपा द्वारा बनाया गया नाटक है। इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि पता नहीं यह खबर कहां से आई। मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट के लिए जो वोटिंग होगी उसमें हमारी जीत होगी। इस्तीफे की अफवाह भाजपा फैला रही है। वे सोच रहे होंगे कि इससे कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जो छोटी-मोटी शिकायतें हैं वह भी दूर हो जाएंगी। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जो लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। भाजपा का सदन में बर्ताव उचित नहीं है। यह सरकार आम आदमी, कर्मचारियों व महिलाओं की सरकार है। बीजेपी की ओर से विधायकों को बरगलाकर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वह सफल नहीं होगा। इस लड़ाई को युद्ध की तरह लडूंगा। सीएम ने कहा कि बजट सत्र में हम अपना बहुमत साबित करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

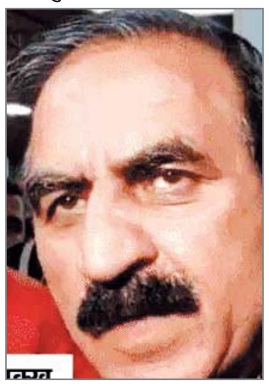

सात फेरे लेने के बाद स्टेज पर बिगड़ी दुल्हन की तबीयत

बैठे-बैठे ही हो गई मौत

फिरोजपुर (एजेंसी)। पंजाब के फिरोजपुर जिले में शादी के दौरान ही एक दुल्हन की मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दूल्हा-दुल्हन के सात फेरे हो गए थे और दुल्हन स्टेज पर बैठी थी। इसी दौरान दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई। 10 मिनट के भीतर लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लोगों ने दुल्हन को होश

में लाने की कोशिश की। डॉक्टरों को बुलाया गया लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ। पलभर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है लो बीपी की वजह से दुल्हन की मौत हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार, फिरोजपुर के गुरहरसहाय के गांव स्वाह वाला में जय चंद की 23 वर्षीय बेटी नीलम की शादी थी। उनकी बेटी को ब्याहने के लिए गांव रुकना बस्ती से महेंद्र कुमार थिंद का बेटा गुरप्रीत बारात लेकर पहुंचा था। घरवालों ने बारात का स्वागत धूमधाम से किया।

बड़ी तैयारी! मार्च से लागू हो सकता है सीएए ऐक्ट

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होगा मोदी सरकार का बड़ा फैसला

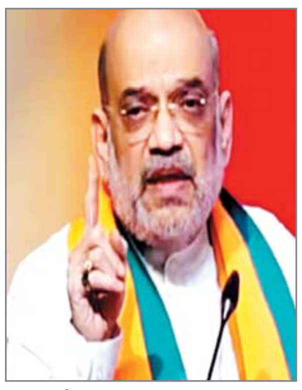

नईदिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून मार्च से लागू करने की तैयारी है। मार्च के पहले सप्ताह में ही लोकसभा चुनाव का भी ऐलान होना है। ऐसे में सरकार आचार संहिता लगने से पहले ही यह बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा। इस नियम के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक पड़ोस के तीन देशों से उत्पीड़न का शिकार होकर आए लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अफगानिस्तान, पाक और बांग्लादेश तीनों ही इस्लामिक मुल्क हैं और यहां हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन पंथ के लोग अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में

लोग दशकों से पलायन करके भारत आते रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ये लोग बसे भी हैं, लेकिन लाखों की इस आबादी के पास भारत की नागरिकता नहीं है। इसके चलते उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को नागरिकता मिलेगी तो वोट देने के अधिकार समेत तमाम चीजों की सुविधा हो जाएगी। यह कानून पहले ही संसद से मंजूर हो गया था, जिसे अब लागू किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली समेत कई राज्यों इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कानून किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे सिर्फ पड़ोसी देशों में पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी, जिनकी स्वाभाविक शरणस्थली भारत ही है। इसकी वजह यह है कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों की शुरुआत भारत से ही हुई थी और कहीं भी इन धर्मों के लोग पीड़ित होने पर भारत की ओर ही देखते हैं। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए इस कानून को लाया गया है।

उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 1 और 2 मार्च को

- भोपाल, इन्दौर, उज्जैन सहित 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट का होगा भूमि-पूजन और लोकार्पण

भोपाल। उज्जैन में 1 व 2 मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव कुल 56 प्रोजेक्ट का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इन्दौर सहित 20 जिलों में हैं। इन 56 प्रोजेक्ट से 74 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक 35 कंपनियों से 74 हजार 711 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। यह आंकड़ा कॉन्क्लेव तक और बढ़ेगा। कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स शामिल होंगे।

काम करते नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने आते हैं

चीनी झंडा देखकर तमिलनाडु में डीएमके पर भड़के पीएम मोदी

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में इसरो से जुड़े एक विज्ञापन पर चीनी झंडा प्रकाशित होने से बवाल मचा हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में डीएमके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए कि डीएमके काम नहीं करती, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने भी सवाल उठाए थे कि डीएमके लंबे समय से इसरो का अपमान करती रही है। खबर है कि डीएमके सरकार में मंत्री थिरु अनीता राधाकृष्ण ने की तरफ से एक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित कराया गया। इसमें सामने पीएम मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की

तस्वीर है। इसमें पीछे एक रॉकेट नजर आ रहा है, जिस पर सबसे ऊपर चीन का झंडा बना हुआ है। पोस्टर में सीएम के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, डीएमके एक ऐसी पार्टी है, जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। यह कौन नहीं जानता कि हमारी स्कीम पर अपने स्टीकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्चपैड का क्रेडिट लेने के लिए इनका स्टीकर चिपका दिया है। ये तमिलनाडु डीएमके के नेता... अब देख ही नहीं सकते...। भारत की प्रगति इन्हें पसंद नहीं।

शिवराज-सिंधिया पर बीजेपी खेलेगी बड़ा दांव!

विजयवर्गीय भी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव

भोपाल (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी में राज्य की 29 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन भी मंगलवार को हुआ है। खबरें हैं कि प्रदेश नेतृत्व नामों की सूची लेकर दिल्ली जा सकता है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2024 चुनाव में भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा दांव खेल सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पार्टी करीब 21 सांसदों को बदल सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट मार्च के पहले वीक में

भोपाल। लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की 29 सीटों में से किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर रायशुमारी के लिए बीजेपी में मंगलवार को दिनभर मंथन चला। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह विधायक-सांसदों की बैठक हुई। इसके बाद दोपहर में प्रदेश पदाधिकारी, शाम को बीजेपी कोर कमेटी और फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति की बैठक में रायशुमारी के बाद 23 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई।

रिलायंस-डिज्नी बिजनेस की चेयरपर्सन बन सकती हैं नीता अंबानी

दोनों कंपनियों के बीच मर्जर डील साइन, रिलायंस के पास होगा 54 फीसदी शेयर

नई दिल्ली (एजेंसी)। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरमैन नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री और वॉल्ड डिज्नी की मर्जर वाली एंटिटी की चेयरपर्सन हो सकती हैं। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस डील का आधिकारिक ऐलान इस हफ्ते हो सकता है। इस बात जानकारी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस के पास इसके 51 फीसदी से 54, डिज्नी के पास 40 फीसदी, जबकि जेम्स मर्डोक और उदय शंकर की जॉइंट वेंचर कंपनी बोधी ट्री के पास 9 फीसदी की हिस्सेदारी होगी।

पटवारी भर्ती कैंसिल करने की मांग, प्रदर्शनकारी हिरासत में

वल्लभ भवन कूच कर रहे थे; क्लीन चिट पर इसी महीने हुए भर्ती के आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश में पटवारी भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। भोपाल में प्रदर्शन के लिए जुटे अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) गठित कर कराना चाहते हैं। उनका यह भी कहना वे अब दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जुटेंगे। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले अभ्यर्थी भोपाल के एमपी नगर चौराहे पर जुटे। यहां धरना देने के बाद वल्लभ भवन की ओर कूच कर गए। पुलिस ने उन्हें व्यापम चौराहे पर बैरिकेड लगाकर रोक लिया। वे आगे बढ़ने की जिद पर अड़ गए। इस पर पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के नजदीक कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। हिरासत में लिए जाने पर प्रदर्शनकारी बोले कि पूरे प्रदेश के छात्र यहां जुटेंगे। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। युवाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा। इंदौर की ललिता को हिरासत में लिया गया है।

ईडी किसी को भी बुला सकती है, उसको है अधिकार

- सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है, तो उसे समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी

देना होगा। खास बात है कि कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगातार 8 समन छोड़े जाने की चर्चाएं हैं। शीर्ष न्यायालय में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ ईडी ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कथित रेत खनन घोटाला में तमिलनाडु के के 5 डीएम को जारी समन पर रोक लगा दी थी।

भोपाल में कांग्रेस की कैंडल लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस

स्कूल शिक्षा विभाग में टैक्सी घोटाले का लगाया बड़ा आरोप, इनोवा के नाम पर स्कॉर्पियो का किराया दिया

भोपाल। कांग्रेस ने स्कूल शिक्षा विभाग में वाहन बिल घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने कहा, तत्कालीन विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार के स्टाफ के लिए इस्तेमाल 6 वाहनों के बिल में फर्जीवाड़ा किया गया। एक वाहन के लिए 13 महीने में 8,62,236 रुपए का भुगतान हुआ। राज्य शिक्षा केंद्र में इस गाड़ी का नाम मारुति सियाज और रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी04-सीडब्ल्यू-9950 दर्ज है। परिवहन विभाग से पता करने पर यह रजिस्ट्रेशन

नंबर हुंडई क्रेटा को अलॉट मिला। यही नहीं, मंत्री के नाम पर आवंटित एक अन्य वाहन को 11 महीने में कुल 17,92,133 रुपए का भुगतान किया गया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने बुधवार को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विभाग-प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया और आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन भी शामिल रहे। खास बात यह रही कि इन नेताओं ने बिजली न होने पर मोमबत्ती की रोशनी में अपनी बात रखी।

दैनिक सद्भावना पाती

इंदौर, गुरुवार 29 फरवरी, 2024

आवास का सपना हुआ सपना सच, हितग्राही श्री राम सिंह के परिवार का बदल गया जीवन

विदिशा (निप्र)। ग्राम बांसखेडी अजीत की है जो कि जनपद पंचायत सिरोंज विकासखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है, जिसमें हितग्राही श्री राम सिंह पुत्र करण सिंह जाति खैरवार अजजा वर्ग है। जिसे वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रमीण से लाभांवित किया गया है।

श्री राम सिंह पुत्र कारण सिंह द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत खेजडागोपाल ग्राम बांसखेडी अजीत जो कि विकासखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है वे परिवार सहित खेती हर मजदूरी करते है परिवार में कुल 04 सदस्य है पति - पत्नी, 01 पुत्र एवं पुत्री निवासरत है, रहने के लिये एक कच्चा मकान था जिसमें एक कमरा एवं एक कच्ची झोपडी थी जिसमें करीब 25 वर्षों से रह रहा थे उसमें जीवन यापन करने में बहुत कठिनाईयां होती थी बरसात के समय निरंतर छप्पर से पानी गिरता रहता था एवं कच्चे मकान में गंदगी एवं मच्छरों के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होने का खतरा हमेशा बना रहता था। यदि कोई मेहमान घर पर आ जाता था तो पडोसी के यहां सोने की व्यवस्था करनी पडती थी जिससे शर्मिदंगी महसूस होती थी। बच्चे के भरण पोषण में ही पूरी आमदानी खर्च हो जाती थी मन ही मन सोचता रहता था कि कभी मेरा पक्का मकान होगा या नहीं? वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ हुआ वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत को 54 आवास को लक्ष्य प्राप्त हुआ फिर धीरे- धीरे ग्रामीणों को योजना की जानकारी प्राप्त हुई जिसमें शासन द्वारा 1.20 लाख रूपये एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत 90 दिवस की मजूदरी के साथ पक्के छत वाले आवास हेतु प्रदाय किये जा रहे हैं। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्ग का व्यक्ति जो एक कच्चे मकान को एक छत वाला मकान बनाने का सपना देख रहे थे उनका सपना सच होते दिखाई दे रहा था। फिर इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में श्री राम सिंह पुत्र करण सिंह को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभ दिलाये जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा चयन किया गया। जब श्री राम सिंह का इस बात का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और पक्के छत का जो सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता था वह सपना उनका पूरा होते ही दिखाई देने लगा।

यह उनके लिये किसी चमत्कार से कम नहीं था मानों मेरी मन की बात भगवान ने सुन ली उसके बाद आवास स्वीकृति उपरांत प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रूपये प्रदाय किये गये जिसे प्राप्त कर हितग्राही द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया इसी प्रकार द्वितीय किश्त के रूप में 40 हजार रूपये एवं तृतीय किश्त के रूप में 25 हजार रूपये तथा मनरेगा की मजदूरी भी साथ-साथ मिलने के कारण आवास पूर्ण हो गया। आवास पूर्ण होने के उपरांत अंतिम चैथी किश्त 15 हजार रूपये प्राप्त हुयी। इस प्रकार शासन से चार किश्तों के रूप में 1 लाख 20 हजार रूपये मिले एवं मनरेगा योजना अंतर्गत 90 दिवस की मजदूरी प्राप्त हुई है जिससे हितग्राही का पक्के मकान का सपना सच हो गया है। हितग्राही अब पक्के मकान में अपने परिवार सहित हंसी-खुशी रहने लगा हुआ है। हितग्राही राम सिंह का पक्का आवास होने से उनके जीवन में कई परिवर्तन आये जैसे अब उन्हें किसी भी मेहमानध्रिश्तेदारों के सामने शर्मिदंगी महसूस नहीं होती उनके सर पर पक्का छत है जिससे बारिश का पानी परिवार के सदस्यों के उपर नहीं गिरता है पक्का मकान होने से मकान में गंदगी एवं मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों से मेरा परिवार दूर हो गया है एवं उनके जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान भी हुआ है पक्का मकान होने से पडोस व मोहल्ले में मानदृसम्मान भी बढ गया है। बिना किसी समस्या के पक्के मकान में जीवन यापन कर रहे है पहले जैसे वर्षाकाल के दिनों में डर बना रहता था अब वो डर भी नहीं रहा है। श्री राम सिंह पुत्र करण सिंह ने बताया कि पूर्व में कच्चा मकान होने एवं मकान में गंदगी होने एवं मच्छरों के कारण परिवार के सदस्य आये दिन बीमार पडते थे जिससे मेरी इतनी कम आमदानी होने के कारण मैं उनका अच्छी तरह से इलाज भी नहीं करवा पाता था लेकिन शासन द्वारा पक्का मकान मिल जाने मेरा परिवार गंदगी एवं मच्छरों से होने वाली बीमारियों से दूर हो गया है।

श्री राम सिंह पुत्र करण सिंह ने बताया कि उन्हें शासन द्वारा खाद्यान पर्ची, उज्जवला योजना, श्रमिक कार्ड जिससे उन्हें भविष्य में पुत्रियों को विवाह सहायता योजना का लाभ मिल सकेगा, एवं स्वास्थ्य संबंधी योजना का लाभ मिल रहा है। पक्का आवास होने के कारण शासन से प्राप्त योजनाओं (जैसे-खाद्यान पर्ची, उज्जवला योजना, श्रमिक कार्ड) के कारण सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बहुत बदलाब आ गया है।

श्री राम सिंह पुत्र कारण सिंह ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पक्का मकान मिल जाने से उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के स्तर में सुधार हुआ है आज ब जार में उनके परिवार की क्रेडिट बढ गयी है एवं उनके परिवार के सदस्यों का मानसिक विकास भी हुआ है अब उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है जो उन्हें पहले कच्चे वाले मकान होने के कारण होती थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक ऐसी शासन की महत्वाकांक्षी

योजना है जिसके द्वारा गरीब व्यक्तियों को जो कभी अपने पक्का मकान होने वाले सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे वो सपना आज पूरा होता दिखाई दे रहा है इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा ही बदल गया है। पहले के 05 वर्ष पूर्व एवं आज की स्थिति में ग्रामीण अंचलों में 75 प्रतिशत पक्के मकान दिखाई देने लगे है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का ही विकास नहीं हुआ है बल्कि म.प्र. शासन का भी विकास हुआ है।

संक्षिप्त समाचार

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हंडिया में एक्स-रे मशीन की सेवाएं प्रारम्भ हुई

हरदा (निप्र)। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हंडिया में सोमवार से एक्स-रे मशीन की सेवाएं प्रारम्भ हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुँचकर मशीन संचालन व्यवस्था का जायजा लिया। डॉ. सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 300एमए की यह डिजिटल एक्सरे मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हंडिया को प्राप्त हुई है। इस मशीन का इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सीएमएचओ डॉ. सिंह ने बताया कि इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हंडिया में सप्ताह में एक दिवस के लिये डेन्टल सर्जन डॉ. पीयुष दोगने की भी ड्यूटी लगाई गई है। डॉ. दोगने प्रति मंगलवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हंडिया में अपनी सेवाएं देंगे, इससे वहां के नागरिकों को डेन्टल चेकअप संबंधी सुविधाएं भी मिलेगी।

अवैध मदिरा के विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही कर 9 प्रकरण दर्ज किये

हरदा (निप्र)। आबकारी विभाग के दल ने अवैध मदिरा के विक्रय संग्रहण व परिवहन के मामलों में कार्यवाही की है। जिला आबकारी अधिकारी श्री रितेश लाल ने बताया कि उनके विभागीय दल ने वृत हरदा के ग्राम खेड़ीपुरा मोहल्ला, टंकी मोहल्ला व पीलियाखाल तथा वृत टिमरनी के ग्राम भीलगांव, सतपुड़ा ढाबा, शिवा ढाबा, ग्राम कायदा, बांसपानी व मगरधा में दबिश देकर कुल 26 पाव देशी शराब, 4 बियर, 26 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब व 290 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया। उन्होंने बताया कि मुद्देमाल जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कुल 09 प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिए गए। जप्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 36570 रूपये है।

सिकमी खोटनामा पंजीयन के लिये 500 के स्टाम्प की अनिवार्यता नहीं

हरदा (निप्र)। नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद श्री सतीश सिटोके ने बताया कि जिले के सभी किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन के पंजीयन के लिये सिकमी के पंजीयन हेतु 500 रूपये के स्टाम्प की अनिवार्यता नहीं है। उन्होने बताया कि किसान भाई किसी भी पंजीयन केन्द्र पर पूर्व वर्ष की भांति स्टाम्प लगाकर सिकमी खोटनामा का पंजीयन करा सकते है।

किशोर न्याय अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विषय पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। रायसेन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दीपक संकत द्वारा प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। इसके उपरांत यूनिसेफ से सीनियर कंसलटेंट श्री अमरजीत सिंह द्वारा दोनों अधिनियमों के संबंध में पुलिस विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के प्रतिभागियों को विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्या प्रावधान है और क्या-क्या नवीन संशोधन किए गए हैं, इसके बारे में अवगत कराया।

प्रधानमंत्री विदिशा जिले के 131.3961 करोड़ की लागत से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों का लोकार्पण

विदिशा (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 फरवरी को प्रदेश के निर्माण कार्यो का वर्चुअल लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। जिसमें विदिशा जिले के भी 131.3961 करोड़ की लागत से कराए जाने वाले निर्माण कार्यो का लोकार्पण, भूमि पूजन भी शामिल है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से 29 फरवरी को किए जाने वाले लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रमों के संबंध में निर्माण ऐजेन्सी विभागो को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है साथ ही आयोजित कार्यक्रम गरिमामय पूर्ण तरीको से सम्पन्न हो साथ ही ततसंबंध में जारी दिशा निर्देशो का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री जी द्वारा विदिशा जिले के 13 निर्माण कार्यो का भूमि पूजन होगा उनमें गंजबासौदा शहर के रिंग रोड बायपास का भूमिपूजन भी शामिल है उक्त कार्य 83.90 करोड़ की लागत से कराया जाएगा। रिंग रोड बाईपास नई मंडी (बरेठ रोड से मेवली तक वाया स्यावदा, गंज, रजौदा, चैरावर, पचमा, महागौर रेल्वे क्रासिंग (भाग-दो) मार्ग शामिल है। इसके अलावा शमशाबाद विधानसभा अंतर्गत 9 करोड़ 40 लाख ग्राम तिन्सयाई से ग्राम वर्धा मार्ग का भूमिपूजन, एक करोड़ 38 लाख की लागत से बासौदा गुरोद मैन रोड से मढ़िया (मजरा) रोड का भूमि पूजन शामिल है के अलावा बासौदा विधानसभा अंतर्गत एक करोड़ 61 लाख की लागत से करारी से भिदवासर बीटी मार्ग निर्माण, एक करोड़ 2 लाख की लागत से ग्राम गजनई से इमलाधाम बीटी मार्ग निर्माण, एक करोड़ 94 लाख की लागत से ग्राम गजनई से बलराकलां मार्ग का निर्माण, एक करोड़ की लागत से मनौरा हैदरगढ़ मार्ग से बसियागाजर मार्ग निर्माण, 3 करोड़ 5 लाख की लागत से हैदरगढ़ से मृगनाथ धाम मंदिर तक मार्ग निर्माण, दो करोड़ एक लाख की लागत से पुरागोसाई से मंगल आदिवासी के घर तक सीसी रोड निर्माण, 2 करोड़ 68 लाख की लागत से एन.एच. 146 बागरोद से विजयपुर तक मार्ग निर्माण, दो करोड़ 6 लाख की लागत से गंज बासौदा विधानसभा की सड़क ग्राम घटेरा से रमपुरा मार्ग निर्माण, दो करोड़ 21 लाख की लागत से धर्मकांटा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से वैष्णो गार्डन हरदूखेड़ी तक मार्ग निर्माण का भूमि पूजन कार्य शामिल है तथा सिरोंज विकासखंड चितावर में एक करोड़ 47 लाख की लागत से हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी द्वारा विदिशा जिले के जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा उनमें 75 लाख की लागत से सिरोंज विकासखंड में ग्रेवल सडक कुंदन खेड़ी से अंधरेला, 25 लाख की लागत से ग्रेवल सडक निर्माण सिरोंज इमलानी रोड से विशेपुर, 81 लाख की लागत से बासौदा में ग्रेवल सडक निर्माण कार्य बासौदा आगासोद रोड से खरतरी, 3 करोड़ 4 लाख की लागत से सिरोंज में बीटी रोड पीएमजीएसवाय ग्राम घुटुआ मार्ग से टोंकर मार्ग तक, एक करोड़ 73 लाख की लागत से लटेरी में ग्रेवल सडक निर्माण लटेरी शमशाबाद मार्ग से खेरखेड़ी लंबाई 3.80 किलोमीटर लटेरी, एक करोड़ 34 लाख की लागत से सिरोंज में ग्रेवल सडक निर्माण सिरोंज गरेठा रोड से धरमपुर लंबाई 3 किलोमीटर सिरोंज, 09 लाख रुपये की लागत से सिरोंज में ग्रेवल सडक निर्माण सिरोंज अमीरगढ़ गरेठा रोड से पठेरा लंबाई 2 किलोमीटर सिरोंज, 32 लाख रुपए की लागत से सिरोंज में ग्रेवल सडक निर्माण सिरोंज आरोन से सारंगपुर लंबाई 0.60 किलोमीटर सिरोंज, एक करोड़ 38 लाख की लागत से सिरोंज में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन मुगलसराय सिरोंज, एक करोड़ 84 लाख की लागत से नटेरन विकासखंड के ग्राम सोमवारा में 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य, 49 लाख की लागत से नटेरन विकासखंड के ग्राम हिनोतिया माली में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य, 49 लाख की लागत से ग्यारसपुर विकासखंड के ग्राम सौजना में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य तथा एक करोड़ 37 लाख की लागत से गंजबासौदा तहसील के ग्राम राजौदा में आउटडोर खेल स्टेडियम का लोकार्पण कार्य शामिल है।

जिले के 84.42 करोड़ की लागत के 240 निर्माण कार्यो का लोकार्पण, शिलान्यास 29 को

विदिशा , (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 फरवरी को वर्चुअल प्रदेश के निर्माण कार्यो का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे जिसमें विदिशा जिले के 240 कार्य जिनकी लागत 84.42 करोड़ रूपए भी शामिल है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि विदिशा जिले की हरेक विधानसभा में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल किए जाने वाले कार्य का सीधा प्रसारण देखने सुनने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय अर्थात विदिशा विधानसभा का कार्यक्रम रविन्द्रनाथ टेगौर सांस्कृतिक भवन (ऑडिटोरियम) में आयोजित किया गया है इसी प्रकार नगरपालिका, सिरोंज, बासौदा के अलावा नगर परिषद शमशाबाद, कुरवाई एवं लटेरी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि विदिशा सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी की स्वीकृति के उपरांत 37 निर्माण कार्यो का भूमिपूजन सम्मिलित है जिसकी कुल लागत 10.05 करोड़ रूपए है। इसके अलावा जिले की पांचो विधानसभाओं में स्थानीय विधायक श्री अनुशंसा पर जिन निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया जाएगा कि संख्यात्मक व लागत जानकारी इस प्रकार से है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 144 में विधायक श्री मुकेश टण्डन की अनुशंसा पर 15.1 करोड़ की लागत के कुल 70 कार्यो का भूमिपूजन किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 145 के विधायक श्री हरिसिंह रघुवंशी की अनुशंसा पर नौ कार्यो का भूमिपूजन किया जाएगा। जिसकी कुल लागत 15.19 करोड रूपए है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 146 के विधायक श्री हरिसिंह सप्रे की अनुशंसा पर कुल 84 निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया जाएगा जिसकी कुल लागत 15 करोड़ है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 147 के विधायक श्री उमाकांत शर्मा की अनुशंसा पर 14.08 लागत के 23 निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया जाएगा जबकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 148 शमशाबाद के विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीणा की अनुशंसा पर 17 निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया जाएग इन कार्यो की कुल लागत 15 करोड़ रूपए है।

बालिका सम्प्रेषण गृह का प्रभार सौंपा

विदिशा , (निप्र)। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बालिका सम्प्रेषण गृह के अधीक्षिका का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्रीमती आकांक्षा मरावी को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर श्री भार्गव के आदेश का हवाला देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री भरत सिंह राजपूत ने बताया कि वन स्टाप सेन्टर (सखी) की प्रशासक श्रीमती कीर्तिका व्यास अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप कार्यालय अधीक्षक बालिका सम्प्रेषण गृह विदिशा का सम्पूर्ण प्रभार विभागीय सहायक संचालक श्रीमती मरावी को अपने कार्यो के साथ-साथ सौंपा गया है। आगामी पर्यन्त तक उक्त आदेश प्रभावशील रहेगा।

पीएम जनमन मिशन के कार्यो से सहरिया जनजाति लाभाविंत हो रही है

वर्षो की समस्याएं चंद मिनटों में हल हो रही

विदिशा (निप्र)। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन) पीव्हीटीजी मिशन के तहत विदिशा जिले में चिन्हित सहरिया जनजाति बाहुल्य समुदाय के नागरिकों को चिंहित तमाम योजनाओं का लाभ शत् प्रतिशत दिलाया जाना है।कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सहरिया जनजाति समुदाय के नागरिकों को अविलम्ब शासन की मंशा के अनुरूप हित लाभ से लाभान्वित किया जाए इसके लिए विशेष पहल की जा रही है।आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक श्रीमती पारुल जैन ने बताया कि सहरिया समुदाय बस्तियो में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है एक शिविर में कई विभागों के अधिकारियों का समावेश हो रहा है और विभागीय योजनाओं से संबंधित दिक्कतो का समाधान मौके पवर किया जा रहा है। बासौदा अनुविभाग क्षेत्र में सर्वाधिक सहरिया जनजाति की 147 बाहुल्य बस्तियां है इन गांव के रहवासियों को एसडीएम श्री विजय राय की पहल पर अविलम्ब चिन्हित योजनाओं, कार्यक्रमों के साथ-साथ आवागमनों की सहूलियत हेतु सडको का निर्माण कराया जा रहा है। एसडीएम श्री विजय राय ने बताया कि बासौदा अनुविभाग क्षेत्र में सहरिया जनजाति वर्ग के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की विशेष पहल की जा रही है जिसके तहत एक दिन में 150 से अधिक जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए है और उन सबकी ऑन लाइन इंट्री लोकसेवा केन्द्र में की जा रही है इसी प्रकार अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। पीएम जनमन कार्यक्रम शिविरो में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, उज्जवला योजना, पात्रता पर्ची, संबल योजना सहित अन्य का हितलाभ प्रदाय कराने की कार्यवाही शिविर स्थल पर ही पूर्ण की जा रही है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा प्रत्येक अनुविभाग क्षेत्र में आयोजित होने वाले शिविरो की समीक्षा के लिए क्रास मानिटरिंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई है।

गेंहू, चना, सरसों, मसूर का पंजीयन कार्य जारी, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें कृषक बंधु

विदिशा (निप्र)। में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि गेंहू हेतु पंजीयन प्रक्रिया 05 फरवरी से शुरू हुई है जो एक मार्च तक जारी रहेगी। इसी प्रकार चना, मसूर, सरसो को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु पंजीयन कार्य जारी है जिसकी अंतिम तिथि दस मार्च नियत की गई है। जिले के कृषकबंधु 123 पंजीयन केन्द्रो में गेंहू, चना, सरसो, मसूर हेतु पंजीयन करा सकते है। किसान निःशुल्क पंजीयन के लिए तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रए एमपी किसान एप पर किसान पंजीयन एक मार्च 2024 तक निःशुल्क कर सकते हैं। गेंहू के लिए अब तक 30544 ने पंजीयन कराया जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर गेंहू विक्रय हेतु अब तक 30544 किसानों के द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। तहसीलवार हुए पंजीयन की जानकारी तदानुसार विदिशा में 9065, शमशाबाद में 3557, ग्यारसपुर में 2356, नटेरन में 2864, बासौदा में 2247, विदिशा नगर में 1261, गुलाबगंज में 1064, कुरवाई में 1831, लटेरी में 1721, पठारी में 836, सिरोंज में 2001 तथा त्योंदा तहसील में 846 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेंहू विक्रय हेतु पंजीयन कराया है।

चना हेतु 8742 कृषकों ने पंजीयन कराया : समर्थन मूल्य पर चना विक्रय हेतु अब तक 8742 किसानों ने पंजीयन कराया है। तहसीलवार अब तक हुए पंजीयन की जानकारी विदिशा में 2148, शमशाबाद में 322, ग्यारसपुर में 517, नटेरन में 999, बासौदा में 1069 विदिशा नगर में 242, गुलाबगंज में 916, कुरवाई में 700, लटेरी में 496, पठारी में 132, सिरोंज में 998 तथा त्योंदा तहसील में 203 किसानों ने समर्थन मूल्य पर चना विक्रय हेतु पंजीयन कराया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यशाला का आयोजन हुआ

विदिशा , (निप्र)। जिला स्तर पर रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत, जनपद एवं क्लस्टर स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण ,स्वच्छ भारत मिशन की समस्त गतिविधियों एवं स्वच्छता ग्रीन लीफ विषय पर विदिशा के रविंद्र नाथ टैगोर संस्कृत ऑडिटोरियम भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिले के समस्त ग्रामों को ठोस, तरल अवशिष्ट प्रबंधन में शत प्रतिशत शेचुरेशन कर मॉडल ग्राम बनाए जाने हेतु विस्तार से तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। उक्त कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट, जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री पंकज जैन, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समेत समस्त जनपद सीईओ ,समस्त ब्लॉक समन्वयक एसबीएम, एडीईओ, पीसीओ जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, उपयंत्री, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी श्री सौरभ खंडेलवाल एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, ज़िला शिक्षा अधिकारी, ज़िला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग,कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ज़िला परियोजना समन्वयक ज़िला शिक्षा केन्द्र ,सहित जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, परियोजना अधिकारी पंचायत राज, परियोजना अधिकारी आवास, परियोजना अधिकारी वाटर शेड, परियोजना अधिकारी मनरेगा/निर्माण , जिला प्रबंधक ग्रामीण आजीविका मिशन ,टास्क मैनेजर एमडीएम,

जिला प्रभारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम, समस्त डीएम फेलो, ब्लॉक फेलो एवं एडीसी आकांक्षी कार्यक्रम के द्वारा उक्त कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए गए। इस कार्यशाला में प्रत्येक क्लस्टर से 02 सरपंच, 02 सचिव, 02 ग्राम रोजगार सहायकों, समस्त क्लस्टर के सब इंजीनियर सहित लगभग 450 प्रतिभागियों द्वारा कार्यशाला में सहभागिता की गई है।

मदिरा एकल समूह निष्पादन हेतु निविदा कार्यक्रम जारी

विदिशा , (निप्र)। जिला आबकारी अधिकारी श्री विनय रंगशाही ने बताया कि विदिशा जिले की 74 कम्पोजिट मदिरा दुकानो को सम्मिलित कर एक एकल मदिरा समूह व्हीडीएस/1 वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए आबकारी नीति के प्रावधानो अनुसार निष्पादन ई टेण्डर के माध्यम से कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला निष्पादन समिति द्वारा कलेक्टेटृ के सभागार में किया जाएगा। वर्ष 2024 हेतु ई टेण्डर द्वारा मदिरा दुकान एक एकल समूह के निष्पादन हेतु जारी कार्यक्रम तदानुसार 27 फरवरी की प्रातः दस बजे से चार मार्च 2024 की अपरान्ह दो बजे तक ई टेण्डर हेतु ऑन लाइन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई टेण्डर आफर सबमिट किए जा सकेंगे। चार मार्च की अपरान्ह 2.30 बजे से ई टेण्डर हेतु ऑन लाइन टेण्डर प्रपत्र खोलने की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। टेण्डर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला समिति द्वारा ई टेण्डर के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। जिला आबकारी कार्यालय से ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवसों, अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। ई-टेण्डर से निष्पादन हेतु कोई भी पात्र व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कन्सॉर्टियम भाग ले सकेगा। ई-टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कन्सॉर्टियम भाग लेना चाहे वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तो एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत ई-टेण्डर के पोर्टल पर आवेदन ध् ऑफर दे सकते है।

दैनिक
सद्भावना पाती
...प्राणियों में सद्भावना हो...

ज़मीन का धंधा सबसे चंगा : तीन साल में पांच गुना तक बढ़े भाव

सबसे ज्यादा उछाल उज्जैन रोड पर; खंडवा रोड, धार रोड, बायपास, पीथमपुर, महू, मानपुर, नेमावर रोड भी पीछे नहीं

कोरोनाकाल में जहां 15 सौ से 18 सौ रुपए का था भाव वहां 5 से 7 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट में मिल रहे प्लाट, यह समय जमीन के धंधे में भारी मुनाफे का दौर

विनय वर्मा

इंदौर। इंदौर की प्राइम लोकेशन पर कोरोना काल में जमीनों के भाव एक दम गिर गए थे लेकिन अब यह व्यापार खूब फल फूल रहा है। जमीन के धंधे में सिर्फ इंदौर ही नहीं वरन बाहर की भी कई कंपनियां तेजी के साथ उतर आई हैं। शहर की सीमाओं से लगी जमीनों पर तेजी से टाऊनशिप आकार लेने लगी हैं।

जमीनों के भाव आसमान छू रहे.....

इंदौर उज्जैन रोड पर जहां कोरोना काल में प्लाट के भाव 6 सौ रुपए से लगाकर 8 सौ रुपए था वहीँ अब तीन से 7 हजार रुपए हो गया है। धार रोड पर जहां 8 सौ से 9 सौ रुपए में प्लाट मिल रहे थे वहीँ अब 27 सौ रुपए से शुरू होकर साढ़े 4 हजार रुपए में भी प्लाट आसानी से नहीं मिल रहे हैं। यही हाल खंडवा रोड, पीथमपुर, महू, मानपुर रोड, नेमावर रोड, इंदौर-देवास बायपास, इंदौर-राऊ बायपास का भी है। यही नहीं अब शहर के बाहर भी नई कालोनी और टाउनशिप डेवलप हो रही है।

प्रॉपर्टी के जानकार अनूप शुक्ला बताते हैं

उज्जैन रोड पर प्रॉपर्टी में बूम इस क्षेत्र में जबरदस्त विकास के कारण आया है। सांवेर रोड से लगाकर धर्मपुरी तक और एमआर 10 से लेकर सुपर कॉरिडोर तक जो विकास हो रहा है उसी के कारण प्रॉपर्टी के भाव में उछाल आया है।

हाईवे इंफ्रा के अरुण जैन का कहना है

इस प्रॉपर्टी के भाव में को बढ़ोतरी हुई है वो इंदौर शहर में हो विकास के कारण है, दूसरा कारण है कि यहाँ की आबोहवा जो बाहरी लोगों को बहुत रास आता है। इसी के कारण लोगों का इन्वेस्ट में भी रुझान है जो कीमतें बढ़ाने में सहायक है।

धार रोड़ पर ज़मीनों के भाव में भारी तेजी आई है

यहां पर रोड़ के नजदीक भाव अधिक हैं जबकि इंटीरियर में अधिक स्थानों पर कॉलोनियां विकसीत हो रही हैं जहां पर प्लाट के भाव भी अधिक हैं। इस क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान जमीनों के भाव बेहद ही कम थे लेकिन आज मुंह मांगी कीमतें मिल रही हैं। रियल एस्टेट के मनीष मित्तल की बात मानी जाए तो इस क्षेत्र में जमीनों के भाव कोरोना काल के बाद आसमान छूने लगे हैं। यहां पर कोरोना काल में 9 सौ से 11 सौ रुपए भाव था वहीं आज 27 सौ रुपए से लेकर साढ़े चार हजार रुपए प्रति वर्ग फीट के भाव पर प्लॉट मिल रहे हैं। कुल मिला कर प्रापर्टी के धंधे में लोग चाँदी काट रहे है।

खंडवा रोड़ पर काम करने वाले प्रापर्टी एजेंट गौरव शर्मा कहते हैं

यह सही है कि कोरोना काल में काम धंधे बिलकुल खत्म हो गए थे जिसके कारण जमीनों के भाव जमीन से भी नीचे चले गए थे लेकिन जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ धीरे धीरे जिंदगी वापस अपने सामान्य दौर में आने लगी और काम धंधे शनै शनै बढ़ना शुरु हो गए और अब हालात ठीक हो गए हैं तो जमीनों के भाव में एकदम से उछाल आ गया है। खंडवा रोड़ पर सिक्स लाइन सड़क के निर्माण और फ्लाय ओवर ब्रिज के कारण प्रापर्टी में जबरदस्त ग्रोथ हुई है।

कमोबेश यही स्थिति इंदौर से राऊ बायपास की भी है

राऊ से महू के बीच कोरोना काल के बाद जमीनों के भाव में भारी उछाल आया है यहां पर जहां कोरोना काल में जमीनों के भाव एक हजार रुपए से 1200 रुपए के बीच थे वहीं अब 3500 रुपए तक पहुंच गए हैं। राऊ महू के किशनगंज में कई कालोनियां विकसीत हो रही हैं जिसके दाम आसमान छू रहे हैं और हालात यह है कि कालोनी के शुरु होते ही प्लॉट की बुकिंग धड़ल्ले से हो रही है। किशनगंज के अनिल वर्मा जिनका ऑफिस मेन रोड़ पर ही है कहते हैं कि कोरोना काल के बाद क्षेत्र में विकास तेजी के साथ हुआ है जिसके कारण इस क्षेत्र में प्लाट की डिमांड भी बढ़ी है यही कारण है कि यहां पर तेजी के साथ भाव भी बढ़े हैं।

पीथमपुर

पीथमपुर प्रदेश ही नहीं वरन देश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां देश विदेश की कई नामी गिरामी कंपनियां अपना कारोबार चला रही है। निश्चित है कि यहां पर जमीनों के भाव में भारी फेरबदल होते ही रहते हैं।

जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ और परिस्थियां सामान्य हुई, प्रोडक्शन के साथ ही यहां का व्यापार भी फलने फूलने लगा और जीवनचर्या में तेजी के साथ बदलाव आया जिसके कारण जमीनों के भाव भी तेजी के साथ ऊपर उठने लगे। पीथमपुर के महेंद्र सिंह बताते है कि कोरोना काल में तो सभी काम धंधे ठप्प हो गए थे तो निश्चित था कि सभी के साथ जमीनों का व्यापार भी ठप्प हो गया था और कुछ लोग तो मजबूरी और जरुरत के लिये जो मिल गया उसी में ओने पौने भाव में जमीन बेचकर निकल गए लेकिन जब जीवन सामान्य हुआ तो धीरे धीरे अन्य कारोबार के साथ जमीनों का कारोबार फिर से चल निकला और भाव तेजी के साथ बढ़ने लगे कुल मिलाकर अभी जमीनों के धंधे में अच्छी उम्मीदें बरकरार है।

आइए समझते हैं किस प्रकार 2020 से अभी तक जमीनों के भाव बढ़े हैं :

इंदौर उज्जैन रोड

2020 में 400 से 600 रुपए
2021 में भाव स्थिर रहे
2022 में 1200 से 1600
2023 में 2700 से 3200
2024 की शुरुआत में ही
3500 से 6000 तक

धार रोड़

2020 में 900 रुपए
2021 में 800 रुपए
2022 में 1100 रुपए
2023 में 2700 रुपए
24 की शुरुआत में 4000 रुपए

खंडवा रोड़

2020 में 1500 रुपए
2021 में 1300 रुपए
2022 में 1800 रुपए
2023 में 2800 रुपए
2024 की शुरुआत में 3200 रुपए

नेमावर रोड़

2020 में 800 रुपए
2021 में 800 रुपए
2022 में 1600 रुपए
2023 में 2500 रुपए
2024 की शुरुआत में 3200 रुपए

इंदौर देवास बायपास

2020 में 1100 से 1900
2021 में 1000 से 1800
2022 में 1500 से 2200
2023 और 2024 की शुरुआत
में 2900 से 7000

राऊ से महू रोड़

2020 में 1000 रुपए
2021 में 900 रुपए
2022 में 1300 रुपए
2023 में 2700 रुपए
2024 में फरवरी में 3500 रुपए

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र

2020 में 4500 रुपए
2021 में 4000 रुपए
2022 में 8000 रुपए
2023 में 17000 रुपए
2024 में 19000 रुपए

महू से मानपुर

2020 में 700 रुपए
2021 में 700 रुपए
2022 में 1100 रुपए
2023 में 1400 रुपए
2024 में 2200 रुपए

देव गुराडिया से सनावदिया

2020 में 500 रुपए
2021 में 500 रुपए
2022 में 800 रुपए
2023 में 1800 रुपए
2024 में 2500 रुपए

नोटः-

उक्त आकडे शासकीय गाईडलाईन अनुसार नही अपितु बाजार मूल्य एवं एजेंटो से प्राप्त किए गए है।

इंदौर में आज भी नर्मदा का पानी नहीं आएगा

इंदौर। नर्मदा लाइन फूटने से पानी की किल्लत से जूझ रहे इंदौर के लोगों के लिए एक और चिंता की खबर है। जलूद लाइन में मंडलेश्वर के पास हुआ लीकेज नहीं सुधर पाया है। लाइन के अंदर लगातार पानी आने से सुधार कार्य प्रभावित हो रहा है। बुधवार शाम तक भी वेल्डिंग शुरू नहीं हो सकी। आशंका है कि गुरुवार को भी पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। नगर निगम के बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर हैं।जानकारी के अनुसार खंडवा के जलूद के पास इंटेकवेल की 2100 एमएम की पाइप लाइन के लीकेज की बात मंगलवार को सामने आई है। वहीं इसका कारण इसकी वेल्डिंग खुलने के कारण पाइप लाइन का फूटना माना जा रहा है। जिस वजह से इंदौर शहर में सुबह 11.50 बजे से नर्मदा के पहले, दूसरे व तीसरे चरण के सारे पंप बंद हो गए है। हालांकि इसके सुधार के लिए प्रशासन ने फुर्ती दिखते हुए इसे ठीक कर पहले व दूसरे चरण के पंप शाम 6 बजे चालू कर दिए थे, लेकिन टंकियों को भरने के लिए जरूरी प्रेशर रात 12 बजे बाद ही आया।

खेतों की फसल बह गई

नर्मदा से लगे मंडलेश्वर क्षेत्र के पहाड़ों से पानी चढ़कर इंदौर आता है। इसका सीधा कनेक्शन इंदौर नर्मदा फेस तीन के कनेक्शन वाले इलाकों से है। मंगलवार को दोपहर में जब पाइप लाइन फूटी तो 50 फीट से अधिक ऊंचा फव्वारा छूट गया। गांव वालों ने बताया कि करीब दो घंटे तक पानी बहता रहा। इस दौरान हजारों गैलन पानी बहकर फिर से नर्मदा में मिल गया। लगभग आधा किलोमीटर तक पानी बहता रहा।

पानी का बहाव इतना अधिक था कि मंडलेश्वर क्षेत्र के कई खेतों में फसल पूरी तरह से बह गई। यहां पर अधिकांश खेतों में इन दिनों गेहूं और चने की फसल लगी हुई है।

सराफा चौपाटी की शिफ्टिंग को लेकर निर्णय मुश्किल में
दुकानदार मांग रहे 56 दुकान जैसे व्यवस्था

इंदौर। सराफा चाट चौपाटी के संचालन के लिए महापौर द्वारा गठित एमआईसी सदस्यों की समिति बुधवार को अपनी रिपोर्ट महापौर को सौंप देगी।

इस रिपोर्ट में समिति ने स्पष्ट कहा है कि सराफा इंदौर की धरोहर है। ऐसे में इसे यहां से शिफ्ट करने का निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजन और आम इंदौरियों का सलाह लेना जरूरी है। ऐसी स्थिति में यह तय है कि सराफा चाट चौपाटी फिलहाल तो शिफ्ट नहीं होगी। समिति ने चाट चौपाटी के दुकानदारों से भी चर्चा की थी। इन दुकानदारों का कहना है कि अगर उन्हें 56 दुकान जैसा विकास करके दिया जाए तो वे यहां से शिफ्ट हो सकते हैं। इधर चाट चौपाटी एसोसिएशन का कहना है कि बाजार में एसोसिएशन के सिर्फ 80 सदस्य हैं, जबकि दुकानें 220 से ज्यादा लग रही हैं। एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा अन्य दुकानदारों को यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। समिति को शिफ्टिंग को लेकर जो अन्य स्थान सुझाए गए थे उनमें संजय सेतू सबसे ऊपर है। इसके अलावा गांधी हाल के पीछे खाली पड़ी जमीन, लालबाग पैलेस के पास, हरसिद्धि, शांतिपथ भी सुझाव में हैं। गांधी हाल के पीछे जो जगह सुझाई गई है वहां पहले से शराब दुकान संचालित हो रही है। इसी तरह लालबाग पैलेस को वर्तमान सराफा से दूर बताकर खारिज किया जा चुका है। हरसिद्धि का क्षेत्रफल बहुत कम है। इसी तरह शांतिपथ पर फिलहाल फिश मार्केट संचालित हो रहा है। संजय सेतु के बारे में कहा जा रहा है कि सड़क की चौड़ाई पर्याप्त है और दोनों तरफ दुकानें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा रिवर साइड रोड पर वाहन पार्किंग की जा सकती है क्योंकि रात के वक्त रिवर साइड बाजार बंद रहता है। एक सुझाव यह भी आया है कि सराफा चाट चौपाटी एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा अन्य दुकानदारों को नया सराफा चौपाटी के नाम से अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए तो भी सराफा की व्यवस्था सुधारी जा सकती है।

लॉरेल्स स्कूल को हाईकोर्ट ने दिया आदेश, शिक्षकों को देना होगा कोरोना काल का पूरा वेतन

इंदौर। लॉरेल्स स्कूल को शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देना होगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश शिक्षकों और अन्य की याचिकाओं का निराकरण करते हुए दिया है।शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल का वेतन मांगने पर स्कूल प्रबंधन ने 12 जून 2021 को पत्र जारी कर उनकी सेवाएं अप्रैल 2020 से ही समाप्त मान ली थी। शिक्षकों और अन्य ने इसे चुनौती देते हुए इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इनमें कहा था कि प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग ने 24 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने के लिए कहा था।स्कूल प्रबंधन ने छात्रों से कोरोना काल की पूरी ट्यूशन फीस वसूल की है। शिक्षकों और अन्य स्टाफ ने भी कोरोना काल में ऑनलाइन सेवाएं जारी रखीं थीं। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन द्वारा वेतन का भुगतान करने से इंकार करने और बगैर किसी सेवा समाप्ति का पत्र दिए एक वर्ष पहले से ही शिक्षकों और स्टाफ की सेवा समाप्त मान ली गई। स्कूल के 16 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं का एक साथ निराकरण करते हुए लारेल्स स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह शिक्षकों और कर्मचारियों को 12 जून 2021 तक के पूरे वेतन का भुगतान करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी नौकरी जारी रखना चाहते हैं वे स्कूल प्रबंधन के समक्ष ज्वाइनिंग दें और स्कूल प्रबंधन इसे तत्काल स्वीकार करे।

इंदौर का बीआरटीएस बनेगा ग्रीन कॉरिडोर

इंदौर। भोपाल का बीआरटीएस बंद हो रहा है वहीं इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यहां चल रही आइ बसों को हटाकर ई बसें (इलेक्ट्रिक बसें) चलाने की तैयारी है। कॉरिडोर के लिए 20 बसें इंदौर आ गई है, जल्द ही और 10 बसें और आ जाएगी और फिर संचालन शुरू हो जाएगा। बस के यात्रियों के मनोरंजन के लिए एआइसीटीएसएल अलग से अटल रेडियो भी लांच करना जा रहा है।

बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए 20 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। सभी के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। जल्द ही 10 बसें और मिल जाएंगी। बसों और सिटी बस स्टॉप पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए जल्द अटल रेडियो भी शुरू किया जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में प्रमुख छह शहरों में पीपीपी मॉडल पर 552 ई बसें (इलेक्ट्रिक बसें) संचालित करने का फैसला हुआ है। इंदौर में एआइसीटीएसएल ने पहले से ही 80 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की प्लानिंग की है। सीईओ मनोज पाठक के मुताबिक, 20 इलेक्ट्रिक बसें कंपनी ने इंदौर पहुंचा दी हैं, इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही 10 बसें और मिल जाएंगी। बीआरटीएस कॉरिडोर पर 12 मीटर की 30 बसें चलाने की योजना है। इलेक्ट्रिक बसें आने के बाद बीआरटीएस से पुरानी बसों को हटाया, जिससे यह ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा। इसके अलावा 50 बसें 9 मीटर की आएंगी, जिन्हें अन्य रूटों पर चलाया जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर शहर को कितनी बसें मिलेंगी, यह अभी साफ नहीं है।एआइसीटीएसएल साथ ही सिटी बस, आई बसों तथा बस स्टॉप पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए अटल रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला है। रेडियो स्टेशन की तैयारी हो गई है, जल्द ही इसे लांच कर दिया जाएगा।

मिल का तालाब बना ट्रेंचिंग ग्राउंड

।इंदौर।

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कुएं, बावडिय़ों और तालाबों का संरक्षण किया जाए। इसके बावजूद शहर के कई वर्षों पुराने तालाबों की स्थिति खराब है। इनमें कल्याण मिल के परिसर का तालाब तो ट्रेंचिंग ग्राउंड में तब्दील हो रहा है। वहां निगम की ही कई गाडिय़ों से बिल्डिंग मटेरियल और कचरा लाकर तालाब में पटका जा रहा है।

शहर के 35 से ज्यादा छोटे-बड़े तालाबों की सफाई का अभियान पिछले दिनों नगर निगम द्वारा चलाया गया था, वहीं सिरपुर तालाब के आसपास भी करोड़ों के कार्य रामसर साइट के चलते किए गए थे। दूसरी ओर कई कुएं-बावडिय़ों की हालत खस्ताहाल है, जहां गंदगी और कचरे के ढेर के कारण लोग भी परेशान हो रहे हैं। वर्षों पुराने कुओं में कचरा डाला जा रहा है। कुछ जगह निगम ने कुओं के आसपास जालियां लगा दी हैं। कुलकर्णी नगर के समीप बने कल्याण मिल परिसर में वर्षों पुराने तालाब में पिछले कुछ दिनों से निगम की हल्ला गाडिय़ों और अन्य वाहनों से मलबा और कचरे का अंबार पटका जा रहा है। वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद वहां कभी अलसुबह तो कभी देर रात को गाडिय़ां पहुंचती हैं और तालाब में कचरा पटक दिया जाता है। नगर निगम ने गत वर्ष भी तालाबों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की थी, मगर उसके बावजूद कई जगह तालाबों की स्थिति बदतर है।

नगर निगम ने वर्षों पुराने अन्नपूर्णा तालाब की सफाई का अभियान शुरू किया है, ताकि वहां फैली गंदगी और जलकुंभी हटाई जा सके। तालाब के संरक्षण को लेकर वहां पहले बाउंड्रीवाल से लेकर कई कार्य किए गए थे, मगर तालाब में फेंके गए कचरे के कारण फिर से स्थिति बदहाल हो गई थी। निगम ने तालाब के आसपास के हिस्से को संवारने के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी तैयार किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते मामले उलझन में ही है।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, गुरुवार 29 फरवरी , 2024

संपादकीय

गरीबी में कमी, लेकिन घरेलू खर्च हो गए दोगुने

अर्थव्यवस्था के तेज विकास और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के दावों के बीच हकीकत यह है कि पिछले बारह-तेरह सालों में लोगों का घरेलू खर्च बढ़ कर दोगुने से अधिक हो गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ताजा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत घरेलू खर्च 2011-12 के 2,630 रुपए से बढ़ कर 2022-23 में दोगुने से अधिक यानी 6,459 रुपए हो गया है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में यह 1,430 रुपए से बढ़कर 3,773 रुपए हो गया है।

इसमें यह भी जाहिर हुआ है कि गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ा है, जबकि खाद्यान्न पर खर्च पहले की तुलना में कम हुआ है। फलों, सब्जियों, दूध, मछली, खाद्य तेल आदि पर खर्च बढ़ा है। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, वस्त्र और दूसरी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च बढ़ा है। इसकी एक वजह तो यह बताई जा रही है कि कोविड के समय शहरों से गांवों की तरफ लौटे लोगों के कृषि क्षेत्र में समाहित हो जाने से उस क्षेत्र का औसत उपभोग खर्च बढ़ा है। मगर यही तर्क शहरी खर्च बढ़ने पर लागू नहीं होता। यह तब है, जब सरकार लगातार महंगाई पर काबू पाने का प्रयास कर रही है।इन आंकड़ों के समांतर दावा यह भी है कि गरीबी में पांच फीसद की कमी आई है। बहुआयामी गरीबी से करीब तेईस करोड़ लोगों के बाहर निकलने का आंकड़ा भी कुछ दिनों पहले चर्चा में था। इन सबके बीच एक तथ्य यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक आय भी लगभग उतनी ही है, जितना प्रति व्यक्ति

मासिक खर्च है।मगर इससे प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति खर्च का समीकरण संतुलित नहीं होता। ज्यादातर परिवारों में एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है, जबकि उस पर निर्भर औसतन तीन लोग होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के बीच सरकार का दावा है कि वह बयासी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है। यानी प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय के औसत में इस आबादी का हिस्सा भी शामिल है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि यह सर्वेक्षण ग्यारह सालों बाद आया है, इसलिए इसमें प्रति व्यक्ति खर्च ऊंचे स्तर पर नजर आ रहा है।

महंगाई और प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ना एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी माना जाता है। मगर इसके साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी समतुल्य बढ़ोतरी दर्ज होना आवश्यक है। विचित्र है कि प्रति व्यक्ति आय उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, जिस अनुपात में महंगाई और घरेलू खर्च बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह रोजगार के नए अवसर सृजित न हो पाना और कोविड के दौरान बाहर हुए लोगों का वापस रोजगार में न लौट पाना है। जो लोग कृषि क्षेत्र में समाहित हो गए हैं, उन्हें भी दैनिक मजदूरी उपलब्ध नहीं हो पाती। कृषि क्षेत्र खुद कई संकटों से गुजर रहा है।

मौसम की मार से फसलों के बर्बाद होने और लागत के अनुपात में फसलों की वाजिब कीमत न मिल पाने की वजह से इस क्षेत्र में मजदूरी घटी है। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में भी काम सौ दिन से घट कर मुश्किल से साल में साठ दिन ही मिल पाता है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि घरेलू खर्च बढ़ने से लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सोशल मीडिया से...

21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गाजा में इजरायल और हमास आतंकियों के बीच चल रहा कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में 28 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर निर्दोष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा में चल रहे नरसंहार से पूरी दुनिया दुखी है और यह चिंताजनक है।

एस जयशंकर, विदेश मंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल यह इंश्योर करेगा कि भारत दुनिया की टॉप-3 इकोनॉमी में पहुंचे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अगली पीढ़ी के लिए रिफॉर्म करना टॉप एजेंडा होगा। अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा।

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

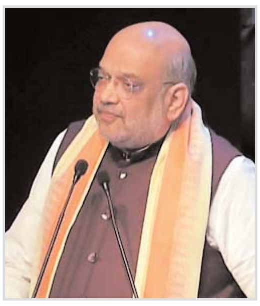

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन किया जा रहा है। इसी मकसद से सरकार ने जम्मू कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध पांच साल और बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

आज का कार्टून

विदेशी चंदे के धंधे पर क्यों है केन्द्र की पैनी नजर?

> विदेशी चंदे का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं को लंबित करने में किया जा रहा है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। इस पैसे का निवेश आंदोलनजीवियों, अराजकतावादियों और प्रदर्शकारियों पर करके जनभावना को भड़काने में किया जा रहा था। ये संस्थाएं समाज के बीच गरीब, दलित, वंचित जैसे असुरक्षित वर्ग की पहचान करती है और इनके आक्रोश को भड़काने पर निवेश करती। इन संस्थाओं का काम देश की फाल्ट लाइन को उभारना है। ईमानदारी से काम करने वाली संस्थाएं कम हैं। उन्हें कई बार पैसों के अभाव से गुजरना होता है। ऐसे एनजीओ जो दलित, आदिवासी, महिलाओं के बीच काम करने के हवाला देकर समाज बांटने के काम में जुड़े हैं, उन्हें मदद करने के लिए देश विरोधी ताकतें खड़ी हो जाती हैं। जिन एनजीओ का एफसीआरए रद्द हुआ है, उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

आशीष कुमार

इसी सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72 साल पुराने प्रमुख थिंक टैंक इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट (आईएसआई) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है। फरवरी में आईएसआई का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया और पिछले महीने जनवरी 2024 में वर्ल्ड विजन इंडिया और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ था। गृह मंत्रालय एनजीओ की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 04 फरवरी तक 20,000 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जिनमें अधिकांश तमिलनाडु से चल रहे एनजीओ थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलाह देने के लिए पहली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) स्थापित की गई थी। एनएसी की ताकत का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में यह बात लोग कहते थे कि एनएसी से यूपीए सरकार नियंत्रित होती है।

एनएसी के सदस्य होने की वजह से हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी की जांच का साहस पिछली सरकार में जांच एजेन्सियां नहीं कर पाई। नई सरकार में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद एफसीआरए के अलग-अलग प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आरोप है कि उनकी संस्था को विदेशी फंड मिलता है। सीबीआई ने उनके एनजीओ के खिलाफ एफसीआरए के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसी महीने 02 फरवरी को उनके एनजीओ से जुड़े परिसरों पर सीबीआई ने रेड डाली है। सीबीआई का दावा है कि इस एनजीओ को जमकर विदेशी फंडिंग मिली है।

विवादों में रहने वाले हर्ष मंदर अपने एक पक्षीय लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुसलमानों के मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई हैं। उनकी संस्था प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रडार पर भी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ पहले से केस दर्ज करके रखा है। 2020 में उनके संचालन में चल रहा एक बाल गृह विवादों में आया था। उस वक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने छापे में वित्तीय और प्रशासनिक दोनों तरह की अनियमितताओं का पता लगाने का दावा किया था।

एफसीआरए को लेकर सरकार अचानक गंभीर नहीं हुई। बताया जाता है कि देश की कई प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों की रिपोर्ट सरकार को मिली थी। जिसमें कई गैर सरकारी संगठनों और उन्हें विदेशों से मिल रहे चंदे को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए गए थे। बताया गया कि देश के कई प्रतिष्ठित एनजीओ और सरकारी सेवा में कार्यरत कुछ अधिकारी विदेशी पैसा लेकर, उसे देशविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं।

विदेशी चंदे का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं को लंबित करने में किया जा रहा है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। इस पैसे का निवेश आंदोलनजीवियों, अराजकतावादियों और प्रदर्शकारियों पर करके जनभावना को भड़काने में किया जा रहा था। ये संस्थाएं समाज के बीच गरीब, दलित, वंचित जैसे असुरक्षित वर्ग की पहचान करती हैं और इनके आक्रोश को भड़काने पर निवेश करती। इन संस्थाओं का काम देश की फाल्ट लाइन को उभारना है। ईमानदारी से काम करने वाली संस्थाएं कम हैं। उन्हें कई बार पैसों के अभाव से गुजरना होता है।

ऐसे एनजीओ जो दलित, आदिवासी, महिलाओं के बीच काम करने के हवाला देकर समाज बांटने के काम में जुड़े हैं, उन्हें मदद करने के लिए देश विरोधी ताकतें खड़ी हो जाती हैं। जिन एनजीओ का एफसीआरए रद्द हुआ है, उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

इन गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि सरकार का एफसीआरए रद्द करने वाला कदम सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाली आवाज़ों को दबाने और नागरिक समाज संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का एक साधन है। समाज के असुरक्षित वर्गो के बीच काम करने वाले संगठनों का कहना है कि वे पैसों की कमी के कारण अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में समाज के बीच काम करना उनके लिए कठिन हो रहा है। कोई भी सरकार उन संगठनों को प्रोत्साहित कैसे कर सकती है जो विदेशों से आए धन को देश की तरक्की के लिए उपयोगी योजनाओं को लंबित कराने में कर रहे हों, जनभावनाओं को भड़काने में कर रहे हों? यह सिर्फ दावा भर नहीं है, इनका सुराग जांच एजेन्सियों को मिला है।

विदेशी पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण को बढ़ाने में भी किया गया है। कई क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बीते दस पन्द्रह सालों में पूरी तरह से बदली है। यह बदलाव स्वाभाविक तरीके से नहीं हुआ। हल्द्वानी का उदाहरण हमारे सामने है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए गई प्रशासन की टीम पर हमला हुआ।

उल्लेखनीय है कि यहां हमलावरों के पक्ष में एनजीओ वाले चेहरे ही दिखाई पड़े। एनजीओ वालों ने सवाल खड़े किए कि कथित हमलावरों को विस्थापित किया गया तो वे कहां जाएंगे? जबकि सवाल कहां जाएंगे कि जगह यह होना चाहिए था कि आए कहां से हैं? भारत के किसी हिस्से से या फिर सरहद पार करके?

एफसीआरए के धन से जुड़े षडयंत्रों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी चंदे पर पारदर्शिता को लेकर गृह मंत्रालय सावधान हुआ। ऐसे मामलों में धांधली बंद करने के लिए एफसीआरए संशोधन से जुड़ा एक विधेयक पारित किया गया। बीते दो सालों (1 जनवरी 2022) से ऐसे गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कानून का असर दिखने लगा।

वर्ष 2021 में 22,762 संगठन एफसीआरए में पंजीकृत थे, कानून लागू होने के बाद एक जनवरी को ये संख्या घटकर 16,829 रह गई। अब संगठनों के पास एफसीआरए बचाए रखने का एक ही सूत्र है कि अपने कामकाज में वे पारदर्शिता लाएं। नए कानून में यह भी शामिल है कि एफसीआरए के अन्तर्गत यदि आपका एनजीओ पंजीकृत है तो आपकी संस्था को मिले विदेशी धन का इस्तेमाल कर बनाई गई किसी भी प्रकार की संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा।

वर्तमान में जांच एजेन्सियों की नजर एफसीआरए के माध्यम से विदेशों से बड़ी रकम इकट्ठा कर रहे उन एनजीओ पर है, जो संस्था का इस्तेमाल हवाला कारोबार अथवा कर की चोरी में मदद पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। या फिर फंड डायवर्जन कर रहे हैं। पैसा शिक्षा में सुधार के लिए लेकर अभ्यर्थियों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाने पर खर्च कर रहे हैं। सरकार के विरोध में चल रहे आंदोलनों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं या फिर वे धार्मिक कन्वर्जन में सक्रिय हैं। यदि ऐसे किसी भी काम में एफसीआरए मे माध्यम से पैसा लेकर कोई एनजीओ जुटा हुआ है तो इतना तय है कि वह देश की जांच एजेन्सियों की रडार पर है।

कैमरे ने सभी को अपनी तस्वीर तैयार करने वाले विशेषज्ञ बना दिए

> आज कैमरा भले सर्वव्यापी दिख रहा हो, मगर शुरू में यह एक चमत्कारी आविष्कार था, जिसने हमारे जीवन का दस्तावेजीकरण करने और यादें साझा करने के तरीके को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। इसमें सबसे सुंदर क्षणों को कैद करने, समय को स्थिर रखने और हमारी बेतुकी हरकतों को चिरस्थायी रखने की शक्ति है। कैमरे से अब केवल विशेष अवसरों की तस्वीरें ही संरक्षित नहीं की जातीं, बल्कि अब यह आम क्षणों का गवाह भी बन रहा है. इससे अब मनचाहे वक्त को कैद किया जाता है।

एक उदाहरण से सब परिचित हो चुके हैं कि मोबाइल के साथ अभिन्न हो चुके कैमरे ने हम सभी को अपनी तस्वीर तैयार करने वाले विशेषज्ञों में बदल दिया है। हर व्यक्ति हर समय अपने निजी 'पपराजी' उपकरण से लैस होता है। पपराजी उस फोटोग्राफर को कहा जाता है जो अभिनेता, नेता, राजनेता की दिनचर्या के फोटो खींचता है।

क्या हम किसी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक त्वरित तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं? अगर खुद कैमरे का कोण बना सके तो ठीक, वरना फोटोग्राफर सामने खड़ा होगा और सबसे आकर्षक रोशनी के लिए बस कैमरे को झुकाने के साथ एक मुद्रा बनानी होगी और खिंच जाएगी आत्म-महिमा। इसमें भी 'सेल्फी' के लिहाज से देखें तो 'फिल्टर' और संपादन 'ऐप' की अंतहीन शृंखलाओं की चर्चा स्वाभाविक रूप से आती है, जो जादुई रूप से किसी भी साधारण तस्वीर को कला की उत्कृष्टता के रूप में बदल देती है। जब 'फिल्टर' में कुत्ते के कान और सिर पर एक चमकदार प्रभामंडल लगाई जा सकने वाली सुविधा हो तो लोगों को अपने जैसा दिखने की जरूरत ही क्या है?

आखिर जीवन का दस्तावेजीकरण करने का क्या मतलब है, अगर यह सर्वोत्तम आभासी स्व को प्रदर्शित नहीं करता है?

'स्पष्ट' तस्वीर की शृंखला को जानने की कोशिश की जाए तो अगर हमारे भोजन के अनुभवों पर कैमरे के प्रभाव के बारे में बात नहीं हो तो कैमरा दुखी हो जाएगा! केवल भोजन का आनंद लेने के बजाय हमें खाने पर विचार करने से पहले हर कल्पनात्मक कोण से प्रत्येक व्यंजन की तस्वीर खींचनी होती है। भोजन का सावधानीपूर्वक 'दस्तावेजीकरण' करना 'महत्त्वपूर्ण' है, अन्यथा हर किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने नाश्ते में या खाने में क्या खाया था..! खाद्य फोटोग्राफी की बात करते हुए हर भोजन, हर नाश्ते और हर सहज काफी के वक्त का 'दस्तावेजीकरण' करने वाले अंतहीन सोशल मीडिया पोस्ट को कैसे भूला जा सकता है? हम सभी शौकिया खाद्य आलोचक और पेशेवर खाद्य फोटोग्राफर बन गए हैं।

'प्रभावशाली लोगों' के उदय के साथ फोटो खींचने की लत और अधिक बढ़ गई है। इस कारण ऐसे प्रभावशाली लोग आत्म-प्रचार की कला को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं और बड़ी संख्या में 'अनुयायियों' को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि उनका जीवन कभी न खत्म होने वाली छुट्टियों से कम नहीं है। इस बीच 'टैगिंग' का रोमांच भी आता है। अच्छे मनोरंजन के नाम पर सबसे समझौतावादी, अप्रिय क्षणों में दोस्तों की तस्वीरें कैद करना और साझा करना।

किसी के सोशल मीडिया खाते पर नजर दौड़ाने और छींक आने के बीच में किसी आनंदमय तस्वीर पर ठोकर खाने की खुशी और किसी तरह सिर पर किसी ने 'वी शेप' यानी जीत के इशारे वाली की दो अंगुलियां धर दीं! समय अब ऐसा आ चुका है कि हम केवल जीवन का अनुभव करने से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमें भावी पीढ़ी के लिए भी इसे सावधानीपूर्वक संभालकर रखना पड़ रहा है। भले ही कोई वास्तव में बिल्ली की जम्हाई लेते हुए 'दो सौ तिहत्तरवीं' तस्वीर देखना चाहता हो या फिर नहीं।

अगली शृंखला में वैसे लोगों को देखा जा सकता है जो चालाकी से खुद को फोटो की पृष्ठभूमि में छिपा लेते हैं और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनपेक्षित प्रफुल्लता प्राप्त होती है। चाहे वे फोटो में अंगूठा दिखाते हों या फिर एक नासमझ चेहरा! ऐसे लोग आमतौर पर छिपे रहते हैं और अपनी हरकतों से किसी की स्थिर तस्वीर पर हावी होने के लिए तैयार रहते हैं। निगरानी और निरंतर दस्तावेजीकरण के इस युग में हम अपनी हर गतिविधि पर नजर रखने वाले सुरक्षा कैमरों की उपस्थिति के आदी हो गए हैं। यह लगभग वैसा ही है, जैसे हम सभी अपने 'रियलिटी टीवी शो' के अनजाने सितारे हैं, जो अदृश्य दर्शकों द्वारा चुपचाप देखे जाने के बावजूद अपना जीवन जी रहे हैं। आजकल ड्रोन फोटोग्राफी की बढ़ती मांग को देखकर इसे नजरअंदाज करना कठिन हो गया है।

इन हवाई कैमरों ने सचमुच ताक-झांक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब हम केवल जमीन से जीवन का दस्तावेजीकरण करने से संतुष्ट नहीं हैं, अब हमारे पास अपने पड़ोसियों की जासूसी करने या बिना सोचे-समझे धूप सेंकने वालों के गुप्त हवाई फोटो लेने की क्षमता आ गई है। ऊपर से गूंजते हुए ड्रोन द्वारा निगरानी किए जाने से बेहतर कुछ भी 'स्वतंत्रता' नहीं है। कैमरे ने हमारे आसपास की दुनिया को कैद करने और साझा करने की अपनी शक्ति के साथ हमारे जीवन को कई बेतुके और प्रफुल्लित करने वाले तरीकों से बदल दिया है। हालांकि इसने निश्चित रूप से हमें एक-दूसरे के करीब ला दिया है और हमें अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम बनाया है। इसने हमें जुनूनी, निगरानी के प्रति जागरूक और अंतहीन तस्वीरें खींचने वाले व्यक्तियों के समाज में भी बदल दिया है। फिर भी कम से कम हमारे पास बुजुर्ग और झुर्रीदार होने पर देखने के लिए कुछ बेहतरीन तस्वीरें होंगी!

संक्षिप्त समाचार

2 साल में 20 प्रतिशत महंगे हुए मकान

- फिर भी तेज बनी हुई है घरों की डिमांड

नईदिल्ली, एजेंसी। मजबूत मांग के दम पर देश में मकान की कीमतें बेहिसाब तेजी से बढ़ रही हैं। बीते 2 साल के दौरान देश में मकान 20 फीसदी महंगे हो गए हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए अपने घर के सपने को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि दाम बेतहाशा बढ़ने के बाद भी मकानों की डिमांड मजबूत बनी हुई है। क्रेडाई और कोलियर्स लियासेज फोराज की हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2023 के दौरान मकानों की कीमतों में 20 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। रिपोर्ट बताती है कि मकानों की कीमतों में 2 साल के दौरान आई 20 फीसदी की इस तेजी का कारण डिमांड में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

है। बेंगलुरू में सबसे ज्यादा बढ़े घरों के दाम रिपोर्ट के अनुसार, देश के टॉप-8 शहरों में मकानों की कीमतों में 2021 से 2023 के दौरान करीब 20 फीसदी की तेजी आई है। मकानों के दाम इस दौरान सबसे ज्यादा बेंगलुरू, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता में बढ़े हैं। इन तीन शहरों में बीते 2 साल के दौरान मकान करीब 30 फीसदी महंगे हो गए हैं। सबसे ज्यादा 31 फीसदी की तेजी बेंगलुरू में आई है। सिर्फ 2023 की बात करें तो टॉप-8 शहरों में सालाना आधार पर मकानों के दाम 9 फीसदी बढ़े हैं।

अनसोल्ड इन्वेंट्री में आई तेज गिरावट- मकानों के दाम में बीते सालों के दौरान आई इस तेजी के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट का कहना है कि घर खरीदारों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। वहीं ब्याज दरें अनुकूल हैं और इकोनॉमिक आउटलुक सकारात्मक है। इन कारणों से हाउसिंग डिमांड मजबूत बनी हुई है और अंतत- सभी प्रमुख शहरों में मकानों के दाम बढ़ रहे हैं। इस डिमांड के चलते अनसोल्ड इन्वेंट्री तेजी से कम हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2023 के दौरान दिल्ली एनसीआर में अनसोल्ड इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा 19 फीसदी की गिरावट आई है।

सोनी प्ले स्टेशन में 900 कर्मचारियों की होगी छंटनी, लंदन स्टूडियो बंद करने की अटकलें

नई दिल्ली, एजेंसी। सोनी प्ले स्टेशन के 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस छंटनी से अमेरिका से लेकर एशिया तक के क्षेत्रों में डिवीजन के लगभग आठ प्रतिशत कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। गौरतलब है कि सोनी लंदन में एक स्टूडियो के बंद करने की भी अटकलें तेज हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के हवाले, वीडियो गेम उद्योग कोविड महामारी के बाद से ही मंदी से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। सोनी गेमिंग के प्रमुख जिम रयान ने वीडियो गेम उद्योग के उत्पादों के विकास, वितरण और लॉन्च के तरीके में बदलाव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमने निष्कर्ष निकाला है कि कड़े फैसले जरूरी हो गए हैं। गौरतलब है कि जिम रयान मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

चीन से पूरी तरह पल्ला झाड़ नहीं सकता भारत

चीन से आयात पर सीमा शुल्क बढ़ने से कई विभागों की बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और चीन के बीच बीते काफी समय से तनातनी है। इसके बावजूद दोनों ट्रेड डिप्लोमेसी से बंधे हैं। कारोबार ने इन्हें जकड़ कर रखा है। इस बीच भारत सरकार चीन से आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने के अपने फैसले के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही है। सरकार के भीतर ही कुछ विभाग मानते हैं कि टैरिफ का इस्तेमाल कूटनीतिक हथियार के रूप में बहुत सोच-विचार कर होना चाहिए। वे इसके लिए किसी हड़बड़ी के पक्ष में नहीं हैं। इसकी वजह है। ऐसी चिंताएं हैं कि भारत की मैन्यूफैक्चरिंग-फोकस्ड स्कीमों जैसे प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम पर इसका प्रतकूिल असर हो सकता है। चीन अभी भी भारत के 14 फीसदी आयात का प्रतिनिधित्व करता है। ड्रैगन न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और चमड़े सहित तमाम उद्योगों के लिए कच्चा माल मुहैया करता है। अलबत्ता, पूंजीगत सामान भी उपलब्ध कराता है। भारत में औसत टैरिफ 2014 में 13 फीसदी से बढ़कर 2022 में 18.1 फीसदी हो गया है। इससे भारत वियतनाम, थाईलैंड और मैक्सिको जैसे देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गया है।

भारत-चीन व्यापार संबंध

सरकार को घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ऊंचे टैरिफ का इस्तेमाल करती है। इसे लागू किए जाने के बाद उसे तमाम मंत्रालयों के विरोध का सामना करना पड़ा है। 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद चीनी आयात पर अंकुश का असर अब इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर दिखने लगा है। इसके कारण घरेलू उत्पादन में कमी आई है। भारतीय मैन्यूफैक्चर्ड वस्तुओं का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ घटा है। एप्पल इंक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉबी समूहों ने चिंता जाहिर की है कि भारत के ऊंचे टैरिफ चीन से सप्लाई चेन को हतोत्साहित करते हैं। वियतनाम, थाईलैंड और मैक्सिको जैसे देशों ने कम्पोनेंट पर कम टैरिफ रखा है। ये उन व्यवसायों को लुभा रहे हैं जो चीन से दूर जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ज्यादा टैरिफ के कारण ऊंची उत्पादन लागत के बारे में चिंता जताई है। सर्किट बोर्ड, चार्जर और पूरी तरह से एसेम्बल्ड फोन सहित पुर्जों पर शुल्क में कमी की गुहार लगाई है। कुछ कटौती पर सहमति बनी है। इसे देखते हुए सरकार ने कई आईटी वस्तुओं पर शुल्क कम कर दिया है। चीन से निम्न-गुणवत्ता वाले आयात पर अंकुश लगाने के प्रयास में भारत ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) लागू किए हैं। ये एमएसएमई के लिए जरूरी कच्चे माल तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। टैरिफ वार्ता में शामिल एक सरकारी अधिकारी ने माना है कि भारत के आयात शुल्क अन्य देशों की तुलना में ज्यादा हैं। अधिकारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ में धीरे-धीरे कमी की जरूरत पर बल दिया है।

चीन के पक्ष में झुका है व्यापार

भारत का चीन के कुल व्यापार में न के बराबर हिस्सा है। लेकिन, वह फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चीनी आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। टैरिफ को धीरे-धीरे कम करना और ग्लोबल बाजारों के साथ बेहतर एकीकरण भारत के विकास और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए ज्यादा लाभकारी नजरिया हो सकता है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की स्टडी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में चीन, थाईलैंड, वियतनाम और मैक्सिको की तुलना में भारत में कच्चे माल पर सबसे ज्यादा टैरिफ है। ऊंचे टैरिफ उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से बराबरी के लिए टैरिफ में कमी की मांग की गई है। एल्यूमीनियम, पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल्स जैसे वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाना उद्योग की ताकत को कम करता है। ऐसी वस्तुओं में भारत काफी संपन्न है। ज्यादा आयात शुल्क भारतीय निर्यात को भी कम प्रतिस्पर्धी बनाता है। इससे घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग में खामियों को बढ़ावा मिलता है। एनडीए सरकार ने 2016 से आयात शुल्क में कई बढ़ोतरी लागू की है। यह आयात शुल्क को कम करने के पिछले ट्रेंड से अलग है। वाणिज्य मंत्रालय इस बात से इनकार करता है कि ये शुल्क बढ़ोतरी संरक्षणवादी है। उसका दावा है कि यह वैश्विक रुझानों के अनुरूप हैं। भारत ने हाल के वर्षों में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने में रुचि दिखाई है। हालांकि, विश्लेषकों ने आगाह किया है कि कुछ प्रस्तावित सीमा शुल्क बढ़ोतरी डब्ल्यूटीओ-अनिवार्यता के करीब है या उससे अधिक हो गई है।

अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज से होगी डीलिस्ट

कंपनी ने दी जानकारी

हिंदुजा ग्रुप, रिलायंस कैपिटल को खरीदेगा

दिवाला प्रक्रिया के तहत हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपए में बोली जीती है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। आईआईएचएल ने कर्ज के बोझ से दबी रिलायंस कैपिटल की बिक्री के लिए दिवाला प्रक्रिया के तहत दूसरे दौर की नीलामी में यह बोली लगाई थी। एनसीएलटी की तरफ से स्वीकृत कर्ज समाधान योजना में कंपनी के कर्जदाताओं को 63 प्रतिशत का तगड़ा नुकसान यानी 'हेयरकट' झेलना होगा।

नईदिल्ली, एजेंसी। देश के सबसे रईस कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की भारी कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल शेयर बाजार से डिलिस्ट होने वाली है। कंपनी की ओर से बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी गई। बता दें, रिलायंस कैपिटल दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है।

शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि एनसीएलटी द्वारा कंपनी के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद कंपनी अपने मौजूदा स्टॉक्स को शेयर बाजार से हटाने पर विचार कर रही है। आगे कहा कि ये कदम आने वाले निवेशक के द्वारा कंपनी में न्यूनतम शेयर होल्डिंग हासिल करने के लिए लिया गया है। रिलायंस कैपिटल के शेयरों में 26 फरवरी 2024 यानी इसी सोमवार से ट्रेडिंग बंद है।

सभी शेयर होंगे रद्द

सेबी के स्टॉक के डिलिस्टिंग और एनसीएलटी के नियमों के मुताबिक ही रिलायंस कैपिटल के शेयर को डिलिस्ट किया जाएगा। लिक्विडेशन के समय रिलायंस कैपिटल के शेयरधारकों की इक्विटी वैल्यू को जीरो माना जाएगा। इसका मतलब है कि डिलिस्टिंग के लिए शेयरधारकों को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

37 साल पहले धीरूभाई अंबानी ने खड़ी की थी कंपनी

रिलायंस समूह के संस्थापक धीरूभाई अंबानी ने इस कंपनी को 37 साल पहले 5 मार्च 1986 को स्थापित किया था। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को 1986 में गुजरात के अहमदाबाद में रिलायंस कैपिटल एंड फाइनेंस ट्रस्ट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। 5 जनवरी 1995 को इसका नाम रिलायंस कैपिटल लागू हुआ।

सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। एसजेवीएन के शेयर आज बुधवार को 1.7 पर्सेंट चढ़कर 124.50 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। कंपनी ने कहा कि उसने गुजरात के बनासकांठा में 100 मेगावाट की राघनेस्डा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू की है। एसजीईएल ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीयूवीएनएल) द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी टैरिफ बोली के माध्यम से इस 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 2.64 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर हासिल किया है। इसके लिए 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्या है डिटेल - 23 फरवरी को एसजेवीएन की सहायक कंपनी ने 300 मेगावाट सोलर एनर्जी कैपासिटी के लिए जम्मू में जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एसजीईएल ने उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी टैरिफ बोली के माध्यम से इस 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 2.98 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर हासिल किया।

एप्पल ने बंद किया अरबों डॉलर का ईवी प्रोजेक्ट

सैकड़ों कर्मचारियों को छंटनी का डर

नईदिल्ली, एजेंसी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अपने अरबों डॉलर वाले इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने अपने इस कार प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी 27 फरवरी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जेफ विलियम्स और वाइस प्रेसिडेंट केविन लिंच द्वारा आंतरिक रूप से इस निर्णय का खुलासा किया गया, जिसने इस प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों को सदमा लगा है।

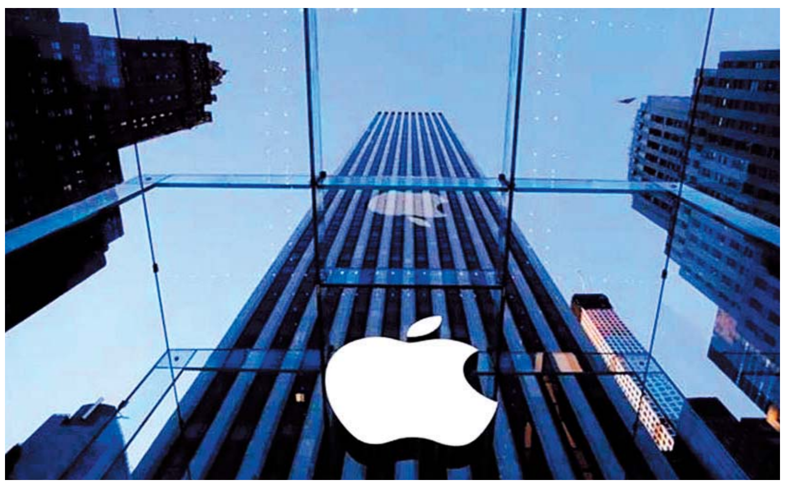

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दी गई है। बता दें कि कंपनी अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट को आने वाले कुछ सालों में टेस्ला को टक्कर देने के लिए बाजार में उतारने वाली थी लेकिन अब कंपनी ने अपने कार प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट को रोक दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी भी करने वाली है।

छंटनी का संकेत

एप्पल ने कथित तौर पर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार परियोजना पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है। ऐसा होने से इस डिवीजन में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों के ऊपर छंटनी का डर मंडरा रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट का सारा काम बंद कर दिया गया है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी संभवत 'टीम से सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर रही है और प्रोजेक्ट पर सारा काम बंद कर दिया गया है।' कुछ कर्मचारियों को एप्पल के जेनरेटिव प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। एप्पल कार प्रोजेक्ट में लगभग 1,400 कर्मचारी थे।

कब लॉन्च होनी थी एप्पल कार?

दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार, जिसे एप्पल कार नाम दिया गया है, के लॉन्च को साल 2026 तक के लिए टाल दिया था। ऐसी उम्मीद थी इस कार की कीमत एक लाख डॉलर से कम होगी। आईफोन बनाने वाली कंपनी का इरादा था कि पहले कार को बिना स्टीयरिंग व्हीकल या पैडल वाला एक ऑटोमोबाइल बनाया जाए, जिससे यात्रियों को लिमोसिन-शैली के वाहन में एक-दूसरे के सामने बैठने की सुविधा मिल सके। पहले की रिपोर्टों के अनुसार, बाद में प्रोजेक्ट का दायरा कम कर दिया गया और ड्राइवर की सीट, स्टीयरिंग व्हील और पैडल के साथ अधिक पारंपरिक डिजाइन तैयार किया गया।

Bitcoin rises 39.7 % in Feb, heads for biggest monthly gain since Dec 2020

Bitcoin inched close to $60,000 on Wednesday, rising 39.7 per cent in February, which would mark its largest monthly rally since December w®w®. Bitcoin was up y.x per cent and was trading at $z~,wyy, its highest since December w®wv. In the last four months, the price of the token has doubled. Moreover, the value of all the Bitcoin in circulation has topped $w trillion this month for the first time in two years. During the bear market in w®ww, when the FTX and other crypto platforms collapsed, the cap had fallen to about $}w® billion.

"This surge can be attributed to the substantial trading activity, totalling $x billion, in Bitcoin spot ETFs, showing increasing demand in the market," added Edul Patel, CEO at Mudre&. The bigger bitcoin e&change-traded funds (ETFs), which were listed in the US on January vv, have seen a definite pick-up in interest this week. The three most popular, run by Grayscale, Fidelity and BlackRock, have seen trading volumes surge, according to Reuters. "Blackrock now has around $| billion in Bitcoin holding and Fidelity has around $z billion, which are phenomenal numbers for a newly launched ETF," said Parth Chaturvedi, investments lead at CoinSwitch Ventures.

Another report suggested that since their launch on January vv this year, the Bitcoin ETFs have attracted investments to the tune of $z.{ billion. Patel said that the surge is also due to the anticipation around the Bitcoin halving, which is e&pected to take place in April. "The approaching Bitcoin halving event, a historical catalyst for price surges, adds to the positive outlook," he said. Bitcoin halving is designed to slow the release of the token, leading to a fall in supply and, subsequently, a rise in its prices. "With daily Bitcoin generation set to fall from ~®® to yz® and constant demand of over w®®® Bitcoin in inflows by the new ETFs, this imbalance will result in price appreciation," Chaturvedi added.

In the coming days, e&perts suggest Bitcoin is poised to top its all-time high of around ${~,®®®.

"Given the current trajectory of increasing demand and optimistic sentiment among investors, there is a strong likelihood that Bitcoin will e&ceed its previous all-time high soon," said Patel. "After the halving event, the supply pressure will increase further and may take Bitcoin value even higher," Thakral said. "We can e&pect Bitcoin to touch the $v®®,®®® mark by the end of w®wy if macroeconomic factors remain favourable."

अडानी ग्रुप का संकट मोचक जीक्यूजी पार्टनर्स बना सबसे बड़ा निवेशक, होल्डिंग्स में एलआईसी को पछाड़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। अडानी ग्रुप के संकट मोचक बने राजीव जैन ग्रुप के अधिकांश शेयरों में धीरे-धीरे अपना निवेश इतना बढ़ाया कि उनकी कंपनी इस अडानी के शेयरों में सबसे बड़ी निवेशक बन गई। करीब 9 अरब डॉलर के शेयरों के साथ त्त्क्त्र पार्टनर्स ने एलआईसी को पीछे छोड़ दिया है। त्त्क्त्र पार्टनर्स ने जहां पिछले छह महीनों में अडानी ग्रुप की अधिकांश कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वहीं देश के सबसे बड़े संस्थागत निवेशक एलआईसी ने अडानी ग्रुप की तीन कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है।

दिसंबर तिमाही के दौरान एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी 1.2 फीसद घटाकर 7.86 प्रतिशत कर दी। जबकि, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में एलआईसी ने क्रमिक रूप से अपनी हिस्सेदारी 3.68 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी। मंगलवार को बंद होने तक अडानी के शेयरों में एलआईसी के शेयरों का मूल्य 63,100 करोड़ था।

केवल दो कंपनियों में निवेश की वैल्यू अब 39,000 करोड़

अडानी ग्रुप की केवल दो कंपनियों में जीक्यूजी पार्टनर्स के निवेश की वैल्यू अब 39,000 करोड़ है। इसकी अडानी पावर में हिस्सेदारी 7.73 प्रतिशत और अडानी ग्रीन एनर्जी में 7.1 प्रतिशत है। इसी तरह अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी इसकी हिस्सेदारी 6.5 प्रतिशत और अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में 3.8 प्रतिशत है। सीएनबीसी-टीवी18 के साथ एक विशेष बातचीत में जीक्यूजी पार्टनर्स के राजीव जैन ने कहा कि ग्रोथ कैपेक्स को कम करना या बढ़ाना आसान है। जब आईआरआर उच्च स्तर पर हो तो पूंजी तक पहुंच कोई समस्या नहीं है। अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी में जीक्यूजी पार्टनर्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इन दोनों स्टॉक्स ने पिछले छह महीनों में ग्रुप की कंपनियों के बीच सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पिछले छह महीनों में दोगुने से अधिक हो गए हैं, इसी अवधि के दौरान अडानी पावर के शेयर में 74 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

00000

बॉस से छुट्टी मांगते वक्त इन बातों का रखें खास ध्यान

बॉस से छुट्टी मांगना आमतौर पर आसान नहीं होता है। कई बार प्लान बनाने से पहले ही सोचना होता है कि छुट्टी कैसे मिलेगी। हालांकि, कई बार छुट्टी लेने के कुछ और तरीकों को भी अपनाकर आप अपने बॉस से लंबी छुट्टी ले सकती हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि जब आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाती हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

प्री प्लान करें

छुट्टी के लिए अचानक से बोलने पर हो सकता है कि आपको छुट्टी नहीं मिले। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको अपने बॉस से पहले से बात कर लेना चाहिए। ऐसे में आपको आसानी से छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा, आपकी गैर-मौजूदगी में आपका काम कौन संभालने वाला है, इसके बारे में भी आपको अपने बॉस से बात कर लेना चाहिए।

बैकअप प्लान करें

लंबी छुट्टी अप्लाई करते समय आपको बैकअप का प्लान तैयार कर लेना चाहिए, ताकि आपकी गैर-मौजूदगी में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो। बैकअप बनाने के बाद अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगी।

छुट्टी का कारण

अगर आपको अचानक छुट्टी चाहिए, तो सॉलिड कारण लेकर ही बॉस के पास छुट्टी मांगने जाना चाहिए। अगर आप यह बोलेंगे कि आपको घूमने जाना है, तो हो सकता है कि आपको छुट्टी न मिल पाए। ऐसे में आपको पहले से कारण तैयार रखना होगा कि आपको अपने बॉस से क्या कहना है।

बॉस का मूड देखकर बात करें

आपको छुट्टी मांगने से पहले अपने बॉस का मूड देख लेना चाहिए। अगर आपके बॉस का मूड अच्छा है, तो आपको तुरंत छुट्टी मिल सकती है। बॉस का मूड खराब होने पर आपको छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है । ऐसे में मूड के हिसाब से ही आपको बात करना चाहिए।

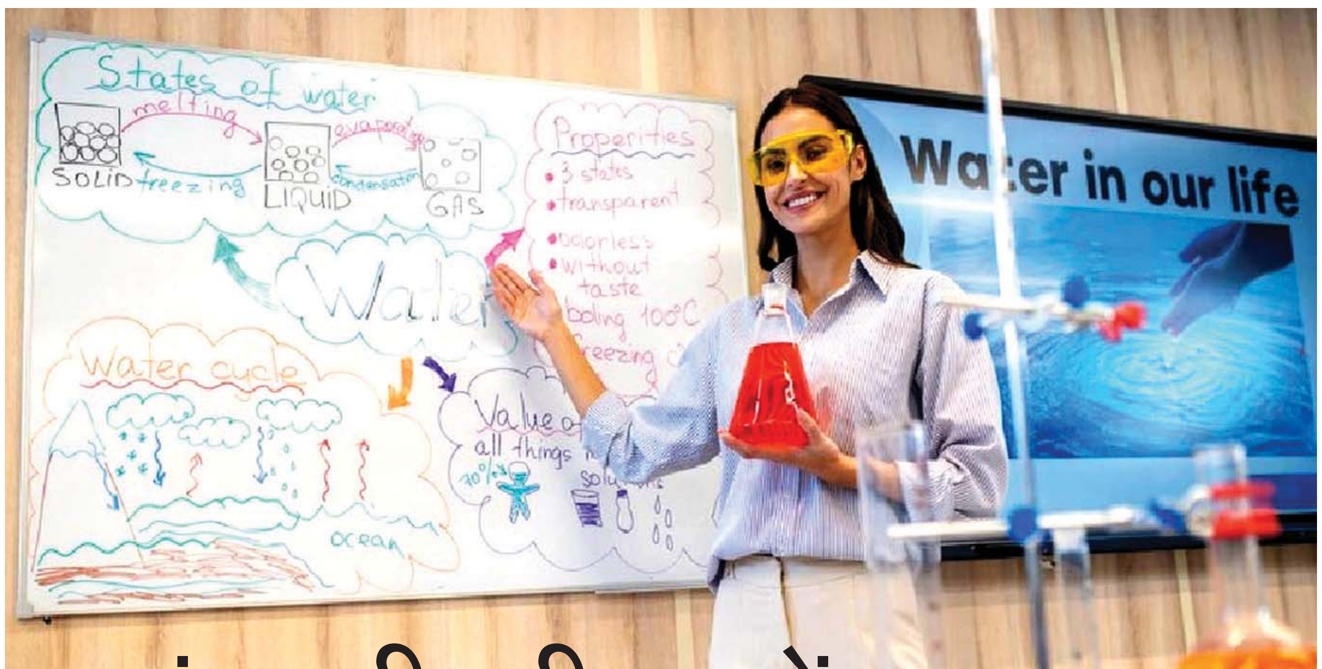

साइंस की फील्ड में ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स हो सकते हैं मालामाल

साइंस के क्षेत्र में अच्छे कोर्स करने के बाद, छात्र मालामाल हो सकते हैं, जो उन्हें अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। यहां कुछ कोर्स हैं जो छात्रों को साइंस क्षेत्र में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इन कोर्स के साथ-साथ, छात्रों को निरंतर अध्ययन करने का प्रैक्टिकल अनुभव भी मिल सकता है।

स्पेस टेक्नोलॉजी

स्पेस टेक्नोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत कॉस्मोलॉजी, स्टारर साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस विषय में डिग्री हासिल करने के बाद आप स्पेस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मैटीरियोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट, रडार टेक्नीशियन, सेटेलाइट टेक्नीशियन आदि के रूप में नासा, इसरो एवं डीआरडीओ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए योग्यता फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स के साथ बारहवीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम पास करने के बाद आप स्पेस साइंस के बैचलर प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। स्नातक के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। आप अगर इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी करना होगा।

कहां से करें कोर्स

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी
- तिरुवनंतपुरम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर।
- आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जरवेशनल साइंसेज,
- नैनीताल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु।

फूड टेक्नोलॉजी

अच्छे खानपान का शौक रखने के साथ फूड प्रोडक्ट में प्रयोग होने वाले रसायनों, खाद्य पदार्थों के रखरखाव, उन्हें पैक करने के तरीकों एवं मार्केटिंग से संबंधित बातों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन कर उभरा है। एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में छात्र फूड प्रोसेसिंग कंपनियों, फूड रिसर्च लेबोरेटरी, होटल, रेस्टोरेंटों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करियर की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या होम साइंस के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद आप फूड साइंस, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। बैचलर डिग्री करने के बाद फूड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अन्य क्षेत्रों में एडवांस डिग्री भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन और फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। स्नातक के बाद परास्नातक व रिसर्च करने का विकल्प भी है।

कहां से करें कोर्स

- सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी
- नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
- राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन
- नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अन्ना यूनिवर्सिटी

मरीन इंजीनियरिंग

मरीन इंजीनियरिंग असल में इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें जहाजों, नावों, पनडुब्बियों और अन्य जलयानों को डिजाइन किया जाता है। मरीन इंजीनियर समुद्री जहाज के सफलतापूर्वक संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं और समुद्र एवं उसके आसपास उपयोग की जाने वाली मशीनों का डिजाइन, रखरखाव, निर्माण करते हैं। इस विषय में डिग्री हासिल करने के बाद आप गवर्नमेंट एवं प्राइवेट शिपिंग कंपनियों, से क्राफ्ट डिजाइनिंग एवं बिल्डिंग, इंजन प्रोडक्शन फर्म में आकर्षक जॉब हासिल कर सकते हैं। मरीन इंजीनियर के लिए भारत और विदेश में भी करियर के अवसरों की एक विस्तृत गुंजाइश है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विभाग में जॉब कर सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

- साइंस बैकग्राउंड के छात्र मरीन इंजीनियरिंग या ओशेन इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक कोर्स के साथ इस करियर में दाखिल हो सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इस विषय में मास्टर्स कर सकते हैं।

कहां से करें कोर्स

- इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, कोलकाता
- आईआईटी मद्रास
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं।

फॉरेंसिक साइंस

फॉरेंसिक साइंस आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी घटना से जुड़े छोटे-छोटे सुराग के जरिये मुजरिम तक पहुंचने और उनसे संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के काम करते हैं। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के छात्र हैं और जुर्म करने वाले को किसी भी हाल में सामने लाने का जुनून रखते हैं, तो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जॉब के मौके उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), स्टेट पुलिस फोर्स के क्राइम सेल, गवर्नमेंट व स्टेट फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते हैं। वहीं, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप चाहें तो फॉरेंसिक टीचर के रूप में भी करियर बना सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

साइंस स्ट्रीम से बारहवीं पास करने के बाद आप फॉरेंसिक साइंस में स्नातक कर सकते हैं। स्नातक के बाद फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, मास्टर करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बी फार्मा, बीडीएस और एप्लाइड साइंस में से किसी एक विषय के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से स्नातक पास करना होगा। अगर आप फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करनी होगी और इसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में एमडी भी करना होगा।

कहां से करें कोर्स

- लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, दिल्ली
- सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हैदराबाद
- सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, चंडीगढ़
- डॉ भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा
- गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी
- बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी

इन संस्थानों से आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी आदि कोर्स कर सकते हैं।

डॉक्टर बनने का रखते हैं सपना तो आज ही नीट यूजी के लिए ऐसे करें अप्लाई

भारत में मेडिकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, उम्मीदवारों को नीट के लिए परीक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होता है, जो कई कैटेगरी से आने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग होती हैं। नीट 2024 में शामिल होने के लिए, उम्मीदवारों को एनटीए के तरफ से तय की गई नीट 2024 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी करनी होगी। चूंकि, इस बार एनटीए ने नीट 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल दी है, इसमें बिना जीव विज्ञान विषय पढ़े छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आयोग ने नीट 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा क्षेत्र के में विस्तार करने का अहम फैसला लिया है। अब, अलग से विषय के तौर पर जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने वाले उम्मीदवार भी नीट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस तरह ऐसे छात्र डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं।

नीट यूजी के लिए स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

- सबसे पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ऑफिसियल वेबसाइट https://neet.nta.nic.in/ पर जाएं।
- अब, वेबसाइट पर "New Registration" के लिंक को सर्च करके क्लिक करें। अपनी पर्सनल जानकारी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। कोशिश करें कि स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी कर लें।
- फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
- इसके बाद "Fill Application Form" के सेक्शन में जाएं और सभी जानकारी सावधानी से भरें। आपको अपनी निजी जानकारी, एकेडमिक एलिजिबिलिटी, एग्जाम सेंटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और सटीक हैं।
- डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10 वीं और 12 वीं की मार्कशीट आदि। अपलोड किए गए डॉक्युमेंट के साइज और फॉर्मेट वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक होनी चाहिए।
- एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें। पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- पूरी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें। फॉर्म में सारी जानकारी सही होने पर "Final Submit" बटन पर क्लिक करें।

जरूरी बातें

- अप्लिकेशन 09 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है।
- अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 मार्च, 2024 है।
- परीक्षा की तारीख 5 मई, 2024 है।
- अप्लिकेशन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें और किसी भी गलती से बचें, वरना अप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
- एप्लीकेशन फीस का पेमेंट समय से पहले ही कर लें।
- सभी जरूरत के डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- एप्लीकेशन जमा करने से पहले उसकी प्रूफरीडिंग कर लें।
- अधिक जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।

इन टिप्स को करें फॉलो

- परीक्षा की तैयारी के लिए NCERT की किताबों को पढ़ें।
- पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करें।
- पेपर से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें।

किसी भी छात्र के लिए उसके करियर ऑप्शन का चयन करना एक बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय है। एक बार जब छात्र अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वे अपने करियर को एक शेप देना चाहते हैं। आर्टर्स में बैचलर डिग्री यानी बीए एक ऐसा कोर्स है, जिसे अधिकतर बच्चे चुनते हैं।

बी.ए. करने के बाद नहीं मिल रही है नौकरी? इन करियर फील्ड में करें ट्राई

आटर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए बीए करना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। हालांकि, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इसमें आप इंग्लिश से लेकर पॉलिटिक्स और मनोविज्ञान तक किसी खास विषय को चुनते हैं। अमूमन यह माना जाता है कि बीए करने के बाद करियर ऑप्शन सीमित हो जाते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आप बीए करने के बाद कई अलग-अलग फील्ड में अपना करियर देख सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि बीए करने के बाद आप किन फील्ड में करियर बना सकते हैं-

जर्नलिज्म में आजमाएं हाथ

बीए करने के बाद एडवरटाइजिंग या जर्नलिज्म की फील्ड में करियर के अवसर देखे जा सकते हैं। आप बीए करने के बाद जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़ा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप टीवी से लेकर रेडियो, अखबार व ऑनलाइन वेबसाइट्स आदि के लिए काम कर सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म, पॉडकास्ट, ब्लॉग और एड आदि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं।

सिविल सर्विसेज की करें तैयारी

अगर आप चाहें तो बीए करने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे यूपीएससी आदि की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा, स्टेट लेवल एग्जाम का हिस्सा बनें। अगर आप इसे क्लीयर कर पाते हैं तो आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बन जाते हैं।

करें प्रोफेशनल राइटिंग

बीए करने के बाद आप प्रोफेशनल राइटिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमा सकते हैं। आमतौर पर, यह एक क्रिएटिव फील्ड है, जिसमें आप अपने विचारों को बेहद ही खास तरह से पेश करते हैं। यदि आपके पास साहित्य में डिग्री है, तो आप निश्चित रूप से क्रिएटिव राइटिंग की फील्ड में काम कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट, से लेकर भाषण, स्क्रीनप्ले, कविताएं आदि लिख सकते हैं। अगर आपका लेखन अच्छा है तो आप प्रोफेशनल राइटिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकती है।

करें लॉ

अगर आप बीए की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो आप बैचलर ऑफ लॉ या एलएलबी चुन सकते हैं। इस तीन साल के कोर्स के बाद आपको लीगल रीजनिंग से लेकर एनवायरनमेंटल लॉ, इंश्योरेंस लॉ आदि की गहन जानकारी हो जाती है। आप चाहें तो इसके बाद एलएलएम भी कर सकते हैं।

करें बिजनेस मैनेजमेंट

बीए करने के बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। यह एक साल का शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसमें छात्रों को अलग-अलग बिजनेस एक्टिविटीज और मैनेजमेंट से जुड़े सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है। इसके बाद आप कई अलग-अलग आर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड

धर्मशाला टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की होगी वापसी?

दो खिलाड़ियों को आराम दे सकते हैं रोहित शर्मा

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में 7 मार्च से खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, सभी भारतीय खिलाड़ी मंगलवार को रांची से रवाना हो गए हैं। बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को 2 मार्च तक चंडीगढ़ में इकट्ठा होने के निर्देश दिए हैं। बुमराह भी टीम के साथ चंडीगढ़ में ही जुड़ेंगे। इसके बाद पूरी टीम 3 मार्च को चार्टेड फ्लाइट के जरिए धर्मशाला पहुंचेगी।

रांची में नहीं खेले थे बुमराह

बता दें कि जसप्रीत बुमराह रांची में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। उन्हें टीम मैनेजमेंट ने वर्कलोड के चलते आराम दिया था। रांची टेस्ट में बुमराह की जगह आकाशदीप का डेब्यू हुआ था। आकाशदीप पहली बार भारतीय टीम में चुने गए थे। उन्होंने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं बुमराह का भी इस सीरीज में अब तक प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 3 मैचों में 13.65 की औसत से 17 विकेट अपने नाम किए हैं।

रोहित करेंगे दो बदलाव

धर्मशाला में पांचवें टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग इलेवन में भी दो बदलाव कर सकते हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित रांची टेस्ट में खेले 11 खिलाड़ियों में से रोहित एक बल्लेबाज और गेंदबाज को आराम दे सकते हैं। बात अगर आराम दिए जाने की आएगी तो यशस्वी जायसवाल को रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि यशस्वी ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं अगर किसी को ड्रॉप किए जाने पर विचार हुआ तो रजत पाटीदार पर भी गाज गिर सकती है।

नहीं खेलेंगे केएल राहुल?

धर्मशाला टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के खेलने पर भी सस्पेंस हैं। हैदराबाद टेस्ट के बाद से ही टीम से बाहर हो गए राहुल चोट का इलाज कराने के लिए इंग्लैंड जा चुके हैं। ऐसे में उनका सीरीज के आखिरी टेस्ट में खेलना काफी मुश्किल है। राहुल को हैदराबाद टेस्ट के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद से वह विशाखापत्तनम, राजकोट और रांची टेस्ट में नहीं खेले।

पाकिस्तानी स्पिनर ने पीएसएल में रचा इतिहास

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान सुपर लीग के 14वें मुकाबले में मंगलवार को शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली लाहौर कलंदर्स सीजन का लगातार छठा मैच हार गई।

मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली मुल्तान सुल्तांस ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन से हरा दिया। मुल्तान की इस जीत में उस्मान खान का बल्ले से और उसामा मीर का गेंद से बहुमूल्य योगदान रहा। उस्मान खान ने 55 गेंद में 96 रन की विस्फोटक पारी खेली थी तो वहीं उसामा मीर ने गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लेकर इतिहास रचने का काम किया। उसामा मीर ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 40 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए।

मीर का यह पीएसएल में बेस्ट बॉलिंग फिगर तो था ही साथ ही वह पीएसएल में 6 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज भी बने। उसामा ने मैच में रासी वैन डैर दुसैन (30), शाहीन अफरीदी (9), जॉर्ज लिंडे (5), कार्लोस ब्रेथवेट (14) जहांदाद खान (0), सलमान फयाज (8) और जमान खान (1) का विकेट चटकाया।

दुबई ओपन : एंडी मरे की हार्डकोर्ट पर 500वीं जीत, दुबई चैंपियनशिप में शापोवालोव को हराया

दुबई, एजेंसी। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने यहां दुबई ड्यूटी फ्री टूर्नामेंट में कनाडा के डेनिस शापोवालोव को तीन सेटों में 4-6, 7-6, 6-3 से हरा दिया। यह हार्डकोर्ट पर उनकी टूर स्तर की 500वीं जीत रही। ओपन युग (1968) में वह ऐसा करने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं। उनके अलावा स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर (783), सर्बिया के नोवाक जोकोविच (700), अमेरिका के आंद्रे अगासी (592) और स्पेन के राफेल नडाल (518) ऐसा कर चुके हैं। हालांकि, पहले दौर में यहां मिली जीत साल में उनकी केवल दूसरी जीत है। पिछले महीने मरे को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पहले दौर में थामस मार्टिन से पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा था। दुबई में मरे ने अपना जीत-हार का रिकॉर्ड बेहतर करते हुए 18-5 कर दिया है। उन्होंने यहां 2017 में ट्रॉफी जीती थी। अब उनकी टक्कर फ्रांस के पांचवीं वरीयता के उगो हमबर्ट या हमवतन वाइल्ड कार्डधारी गेइल मोनफिलिस से होगी।

36 साल के खिलाड़ी ने दिए संन्यास के संकेत

एंडी मरे ने संकेत दिए हैं कि यह उनके लंबे कॅरिअर के अंतिम कुछ माह हो सकते हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के समय भी 36 साल के खिलाड़ी ने कहा था कि यह उनका अंतिम ग्रैंडस्लैम हो सकता है।

दुबई में शापोवालोव को हराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रतियोगी टेनिस में हिस्सा लेना चाहता हूं लेकिन उम्र के लिहाज से अब युवा खिलाड़ियों के साथ खेलना और अपने आपको फिट बनाए रखना आसान नहीं रहा। मेरे लिए अब ज्यादा लंबे समय तक टेनिस खेलना मुश्किल है।

पहला सेट हारने के बाद की रूबलेव ने वापसी

इस बीच आंद्रे रूबलेव ने धीमी शुरुआत से उबरते हुए लगातार पांचवें साल दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पहले दौर में उन्होंने झांग झिझझेन को एक घंटा 51 तक चले मैच में 6-7(4), 6-2, 6-4 से हराया। रूबलेव ने 18 ऐस लगाए और दोनों ब्रेक प्वाइंट बचाए। दुनिया के पांचवें नंबर के खिलाड़ी रूबलेव ने 2022 में दुबई में खिताब जीता था। इसके अलावा पिछले साल वह फाइनल में पहुंचे थे। वह सत्र में अपनी दूसरी ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

ऋषभ पंत के कमबैक को लेकर फैंस उत्साहित

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 से पहले अपने शरीर को बेहतर बनाने और बेहतरीन फिटनेस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिम में पसीना बहा रहे हैं। दिसंबर 2022 के बाद पहली बार क्रिकेट के मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज ने प्रशंसकों को अपने कठोर जिम सत्र की एक झलक दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

पंत 30 दिसंबर, 2022 को एक घातक कार दुर्घटना में बच गए। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में व्यापक पुनर्वास किया है और उनकी रिकवरी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने पहले कहा था कि पंत आईपीएल 2024 में हर मैच खेलने को लेकर बहुत आश्वस्त हैं।

फ्रेंचाइजी के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने भी आशा व्यक्त की कि पंत आईपीएल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे और इस बात पर जोर दिया कि वह शुरू से ही टीम का नेतृत्व करेंगे लेकिन टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में पूरी तरह से बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की प्लेइंग इलेवन

वेलिंगटन, एजेंसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 फरवरी से वेलिंग्टन में शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने वार्नर के संन्यास लेने के बाद स्टीव स्मिथ पर ही फिर से भरोसा कायम रखा है।

स्टीव स्मिथ ही उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही पैट कमिंस ने उसी बॉलिंग यूनिट को बरकरार रखा है जो पिछले 5 टेस्ट से खेलती आ रही है।

पेस बॉलिंग अटैक में कोई चेंज नहीं

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलिंग अटैक की जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और कप्तान पैट कमिंस के कंधों पर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की यह पेस तिकड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दो टेस्ट में खेली थी।

स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी पारी का आगाज करेगी। वहीं मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श मध्य क्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे।

वेलिंग्टन टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड ने अभी प्लेइंग इलेवन की घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि कीवी टीम को प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने होंगे, क्योंकि सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे अंगूठे की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्हें टी20 सीरीज के दौरान चोट लगी थी। कॉनवे के बाहर होने के बाद माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड को टॉप ऑर्डर में बदलाव करना ही होगा। माना जा रहा है कि कॉनवे की जगह विल यंग को टीम में शामिल किया जा सकता है।

पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड।

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

टॉम लैथम, विल यंग, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, टिम साउदी (कप्तान), विल ओ'रूर्के

डेवोन कॉनवे चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे टी20 सीरीज के दौरान अंगूठे में लगी चोट के कारण गुरुवार से यहां सेलो बेसिन रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को बल्लेबाजी कवर के रूप में टीम में बुलाया गया है और वह आज सुबह प्रशिक्षण के लिए वेलिंगटन में टीम में शामिल होंगे। कॉनवे को शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान बाएं अंगूठे में चोट लग गई थी।

विलियमसन बने पिता

पार्टनर सारा ने दिया फूल सी बच्ची को जन्म

नई दिल्ली, एजेंसी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज केन विलियसन तीसरी बार पिता बन चुके हैं। उनकी पार्टनर सारा रहीम ने फूल सी नाजुक बेटी को जन्म दिया है। विलियनसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी और नवजात बेटी के साथ फोटो शेयर करते हुए यह खुशखबरी शेयर की। केन ने तस्वीर के साथ लिखा, और फिर वहां तीन थे। दुनिया में स्वागत है खूबसूरत लड़की। आपके सुरक्षित आगमन और आगे की रोमांचक यात्रा के लिए बहुत आभारी हूं।

दो बेटी, एक बेटे के माता-पिता

दंपति के पहले से ही दो बच्चे थे। बड़ी बेटी तीन साल की है, जिसका नाम मैगी है तो छोटे बेटे की उम्र एक साल है। पितृत्व अवकाश पर होने के कारण विलियमसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालिया टी-20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे। हालांकि, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल की दो टेस्ट मैच की सीरीज में शानदार लय में नजर आए थे, जिससे ब्लैक कैप्स को दक्षिण अफ्रीका पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने में मदद मिली थी।

शानदार फॉर्म में विलियमसन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज की चार पारियों में केन विलियमसन के बल्ले से तीन-तीन शतक निकले। माउंट मॉनगनुई में उन्होंने 118 और 109 रन की पारी खेली तो हैमिल्टन में हुए दूसरे टेस्ट में 43 और नाबाद 133 रन बनाए। इस तरह वह 32 टेस्ट शतकों के साथ सबसे ज्याद टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली सरीखे दिग्गज को पछाड़ते हुए 12वें नंबर पर पहुंच गए।

विराट के घर भी गूंजी किलकारियां

केन विलियमसन और विराट कोहली की दोस्ती जगजाहिर है। दोनों अंडर-19 क्रिकेट के दिनों से दोस्त हैं। मैदान के बाहर दोनों की बॉन्डिंग देखते ही बनती है। अब पर्सनल लाइफ में भी इन स्टार क्रिकेटर्स के घर लगभग एक ही समय पर गुडन्यूज आई है। इसी महीने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी अपने दूसरे बच्चे के माता-पिता बने हैं। बड़ी बेटी वामिका के बाद अब यह पावर कपल एक बेटे के माता-पिता बने हैं, जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा है।

अदा शर्मा ने बस्तर- द नक्सल स्टोरी में नक्सलियों जैसी चाल - ढाल अपनाने के लिए जंगलों में बिताया समय

विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की अगली फिल्म बस्तर- द नक्सल स्टोरी के लिए एक्साटइमेंट तेज है। ऐसा इसिलए क्योंकि इस तीकड़ी ने पहले द केरल स्टोरी जैसी बेहतरीन फिल्म दी हैं। अब साथ में ये बस्तर-द नक्सल स्टोरी लेकर आ रहे हैं जिसके दोनों टीजरों ने पहले ही खूब सुर्खियां बनाई है और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

जहां दर्शकों ने निर्माताओं की एक और बोल्ड कहानी के लिए टीज़र की सराहना की, वहीं अदा शर्मा के लुक को भी लेकर चर्चा हुई। इस फिल्म के टीजर में अदा शर्मा आईपीएस नीरजा माधवन का किरदार निभाती नजर आ रही हैं और जिसके एक्ट्रेस ने जमकर मेहनत की है। सुनने में आया है कि किरदार में खुद को पूरी तरह से ढलने के लिए एक्ट्रेस अदा शर्मा को कड़ी ट्रेनिंग से लेनी पड़ी। नक्सलियों के टोन और बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए एक्ट्रेस को जंगलों में भी रहना पड़ा।

अदा शर्मा ने फिल्म में अपने किरदार की तैयारी के लिए जमीनी लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी। बैटल सीक्वेंस के लिए, उन्होंने बंदूकों और डिफेंसिव हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा, अदा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में एक व्यापक ट्रेनिंग सेशल के लिए यात्रा की और इस दौरान उन्होंने अपने किरदार के लिए सही टोन पाने के लिए कुछ सलाहकारों से भी मुलाकात की। टीज़र को मिली भारी प्रतिक्रिया के बाद मेकर्स ने बहुप्रतीक्षित फिल्म के कैरेक्टर पोस्टर्स की झलक भी लोगों को दे दी है। टीम ने फिल्म के नए पोस्टरों की एक सीरीज साझा की है जो दर्शकों को मुख्य अभिनेताओं और फिल्म में उनके द्वारा निभाए जा रहे किरदारों से रूबरू कराता है। अदा शर्मा की डेडिकेशन इस बात का साफ सबूत है कि विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप्तो सेन फिल्म के हर पहलू को सही करने में विश्वास करते हैं। निर्माता किसी भी पहलू पर समझौता नहीं करते और उनका इरादा एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली और रियल लाइफ बेस्ड त फिल्म पेश करना है। इस फिल्म में निर्माताओं ने कई शहीदों के बारे में सच्चाई उजागर की है और बताया है कि कैसे हमारे देश में सूडो इंटेलेक्चुअल्स चीन के पैसे से देश को तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं।

साथ ही, फिल्म का मकसद उस महत्वपूर्ण आंदोलन पर प्रकाश डालना है जिसका इरादा देश को नक्सल फ्री भारत बनाना है। विपुल अमृतलाल शाह की सनशाइन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और आशिन ए शाह द्वारा सह-निर्मित, बस्तर- द नक्सल स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित हैं और इसमें अदा शर्मा मुख्य भूमिका में होंगी। यह फिल्म 15 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित हुए निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा

12वीं फेल निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच उन्होंने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि कर ली है। हाल ही में उन्हें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारों में महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक प्रभाग द्वारा प्रतिष्ठित राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुस्कार मिलने के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि मेरी जन्मभूमि कश्मीर थी और मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है। कश्मीर और महाराष्ट्र का यह सांस्कृतिक मिश्रण ही, आज मैं हूं। यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिल रहा है। महाराष्ट्र मेरी भूमि है जहां मैं रहता हूं, जहां मैं काम करता हूं और जहां मैं मरना चाहता हूं! मुझे सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

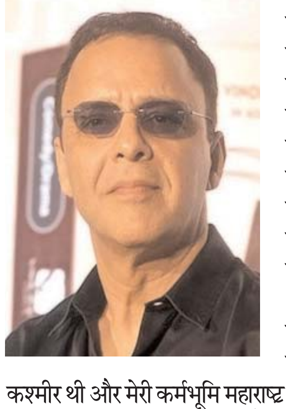

मार्च में सिख और ईसाई धर्म के अनुसार

विवाह बंधन में बंधेगी तापसी पन्नू

बी-टाउन में शादियों का सीजन चल रहा है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंधे। मार्च में पुलकित सम्राट-कृति खरबंदा भी शादी करने वाले हैं। वहीं अब बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस दुल्हन बनने जा रही है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस तापसी पन्नू हैं। एक्ट्रेस तापसी पन्नू हमेशा किसी न किसी कारण से समाचारों में रहती हैं। कभी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की हाईलाइट होती है, तो कभी पर्सनल लाइफ की बात। फिलहाल उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक खास खबर सामने आ रही है। हाल ही एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने फिल्ममेकर जैकी भगनानी के साथ सात फेरे लिए हैं और अब तापसी के फैंस के लिए भी गुडन्यूज है। तापसी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर मैथियास बो के साथ शादी रचाने वाली हैं।

मैथियास 2 बार यूरोपियन चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं। तापसी (36) मैथियास (43) को 10 साल से डेट कर रही हैं। हालांकि तापसी ने इस रिश्ते का कभी प्रचार नहीं किया। बताया जा रहा है कि तापसी मार्च में शादी करेंगी। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में राजस्थान पहली पसंद बना हुआ है और तापसी भी इसी प्रदेश में ब्याह रचाएंगी। वह झीलों की नगर उदयपुर में शादी करेंगी।

रिपोर्ट के मुताबिक तापसी-मैथियास 2 अलग-अलग धर्म सिख और क्रिश्चियन के रीति-रिवाज के हिसाब से शादी करेंगे। उनकी गेस्ट लिस्ट में बॉलीवुड सितारे शामिल नहीं हैं। कपल सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेगा। हालांकि अभी तक कपल ने शादी को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दी है।

सद्भावना पाती

इंदौर, गुरुवार 29 फरवरी , 2024

संक्षिप्त समाचार

आप-कांग्रेस का क्लीनस्वीप करेगी भाजपा?

नईदिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में अपने चार उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने तीन मौजूदा विधायकों पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस के पुराने चेहरे महाबल मिश्रा पर भी भरोसा जताया है। सोमनाथ भारती और सहीराम पहलवान लगातार तीन बार विधानसभा पहुंचे हैं। कुलदीप पहली बार 2020 में कोंडली विधानसभा से विधायक चुने गए। महाबल मिश्रा ने आखिरी चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और हार गए थे। यह उनका चौथा लोकसभा चुनाव हैं। आइए जानते हैं 2019 के चुनाव में तीनों पार्टियों का मत प्रतिशत कितना रहा था दिल्ली में आप का कांग्रेस के साथ यह दूसरा गठबंधन है। पहला गठबंधन 2013 में हुआ था, जब आप ने कांग्रेस विधायकों के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और सरकार 49 दिनों में ही गिर गई। वर्ष 2019 में फिर दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव में साथ आने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों का कहना है कि जो सीटों कांग्रेस के खाते में गई है वह भी उन पर जातिगत समीकरणों के हिसाब से रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही वह भी प्रत्याशी घोषित कर देगी।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट से गुहार, केस चलाने की मांग

नईदिल्ली, एजेंसी। समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक अधिवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अदालत में परिवाद देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। अधिवक्ता ने अर्जी में आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस अर्जी पर एसीजेएम कोर्ट प्रथम ने मामले को थाना साहिबाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने पुलिस को मामले की सत्यता की जांच करने के आदेश दिए हैं। लाजपत नगर में रहने वाले अधिवक्ता साकेत कटारा की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता देवाशीष महर्षि के जरिए दी गई अर्जी में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। अर्जी के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की गुहार लगाई गई है। एसीजेएम कोर्ट प्रथम ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए थाना साहिबाबाद पुलिस को मामले की सत्यता की जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने इसी से मिलते जुलते एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय दिया है।

पानी के बिल पर बढ़ा सियासी बवाल, आप-मुख्य सचिव में बढ़ी तकरार

केजरीवाल के विधायकों का सदन में प्रदर्शन

नईदिल्ली, एजेंसी।
पानी के बिल में छूट को लेकर तैयार की गई वन टाइम सेंटलमेंट योजना पर मंगलवार को विवाद और बढ़ गया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य सचिव को कई बार निर्देश जारी करने के बाद भी अधिकारी इस योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जल बोर्ड की योजना केंद्र सरकार, और एलजी के दबाव में रोकी जा रही है। वहीं, मुख्य सचिव की ओर से लिखे गए एक नोट में दावा किया गया कि इस योजना से संबंधित प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने तैयार ही नहीं किया है।

'अफसरों पर योजना रोकने का दबाव'

शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को पत्रकारवार्ता में कहा कि 40 फीसदी पानी उपभोक्ता गलत बिल से परेशान हैं। राजधानी में कुल 27 लाख उपभोक्ता हैं, लेकिन बिल में गड़बड़ी के चलते 10.5 लाख उपभोक्ता पानी का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। सरकार इसके समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसर दबाव में इस योजना को कैबिनेट में लाने को तैयार नहीं हैं।

आप का सदन में प्रदर्शन

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंगलवार को फिर सत्ता पक्ष के विधायकों ने पानी बिल माफी योजना को रोकने का आरोप लगाते हुए सदन में प्रदर्शन किया।

एलजी से अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का निर्देश देने की मांग की और पैदल मार्च करते हुए सदन से बाहर निकल आए। इसके चलते दो बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में आप विधायक बी. एस. जून ने अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने वाले एक पत्र का जिक्र करते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा।

इस पर सदन के सभी विधायकों का समर्थन मिला तो उस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया। इस दौरान पानी के बिलों का मुद्दा उठा तो सत्ता पक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद विधायक गांधी की प्रतिमा के नीच प्रदर्शन करने लगे। जल बोर्ड उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा कि अगर जनता बढ़े बिलों से परेशान है तो मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो योजना लाकर उनको राहत दें।

दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव तैयार नहीं किया

दिल्ली के मुख्य सचिव की ओर से लिखे गए एक नोट में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार ने पानी के गलत बिलों को ठीक करने का प्रस्ताव अभी तक तैयार ही नहीं किया है। नोट में कहा गया है कि इस योजना से संबंधित फाइल चार माह तक मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास लंबित रही। अब इस फाइल को उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को लौटा दिया है। इस योजना में प्रस्तावित बदलाव को भी जल मंत्री आतिशी द्वारा मंजूरी नहीं मिली है। मुख्य सचिव द्वारा मंत्री सौरभ भारद्वाज को लिखे गए नोट से पता चला है कि 13 जून 2023 को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का निर्णय लिया गया था। 31 अगस्त 2023 को यह फाइल मंजूरी के लिए मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास भेजी गई। चार माह से अधिक समय की देरी के बाद उन्होंने बीते 9 जनवरी को यह फाइल दिल्ली जल बोर्ड को भेजी। उन्होंने जल बोर्ड द्वारा पहले से ही वन टाइम सेटलमेंट योजना के प्रस्ताव पर फिर से काम कर रहा है। बीते 11 जनवरी को सौरव भारद्वाज ने जल बोर्ड को फाइल वापस करने के संबंध में जल मंत्री आतिशी को एक नोट भेजा। दिल्ली जल बोर्ड ने बीते 17 जनवरी को आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। 18 जनवरी को इसके मिनट मंजूरी के लिए जल बोर्ड अध्यक्ष आतिशी के पास भेजे गए। आतिशी ने 18 जनवरी को एक नोट दर्ज किया ,जिसमें बताया गया कि एक महीने में बोर्ड के साथ कई चर्चाएं हुई हैं, लेकिन किसी ठोस बदलाव को औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। जल बोर्ड ने 23 फरवरी को स्टेटस नोट में सूचित किया कि 17 जनवरी को बैठक के मिनट्स आतिशी के पास लंबित हैं।

आवारा कुत्तों ने डेढ़ साल की बच्ची को नोंचकर मार डाला, एनएचआरसी ने सरकार से लिया संज्ञान

नईदिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य दिल्ली के तुगलक लेन में 24 फरवरी को आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा नोंचने से डेढ़ साल के मासूम की मौत मामले पर स्वत संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले पर मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, एनडीएमसी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस प्रमुख को छह हफ्ते में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मासूम बच्ची का नाम दिव्यांशी था। उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि वह धोबी घाट गेट के पास थी जब पांच कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला किया और उसे 100 मीटर दूर खींच लिया। एनएचआरसी ने कहा कि कुछ महीने पहले इसी परिवार के एक बच्चे के साथ इसी तरह की घटना घटी थी, उसके बाद दोबारा ऐसा हमला हुआ है। जबकि क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर निवासियों ने कई शिकायतें की थीं।

मीडिया रिपोर्टों की समीक्षा करने पर, आयोग ने इस स्थिति को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है। पिछली घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए, एनएचआरसी ने सिविक अथॉरिटी को पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार, आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रिवेंशन और क्यूरेटिव कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। इसी बीच एक पशु अधिकार संगठन ने घटना पर सवाल उठाए हैं। प्रेस को दिए एक बयान में, उसने पूछा कि पुलिस घटना के किसी भी प्रत्यक्षदर्शी को क्यों नहीं ढूंढ पाई? उसने संबंधित अधिकारियों से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने का आग्रह किया। इसमें यह भी दावा किया गया कि परिवार के पास एक पालतू कुत्ता है। संगठन ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे उसका हाथ हो सकता है। जवाब में डीसीपी (नई दिल्ली) देवेश महला ने कहा कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लड़की के पिता राहुल कनोजिया ने कहा था कि वह काम से वापस आ रहे थे जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई है।

करीब पांच महीने बाद दिल्ली की हवा हुई साफ, ग्रैप की सभी पाबंदियां हटीं

नईदिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत के चलते केन्द्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रैप की सभी पाबंदियों को हटा लिया है। दिल्ली-एनसीआर में बीते साल छह अक्तूबर को ग्रैप के पहले चरण की पाबंदियों को लागू किया गया था। इससे पहले ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियों को 18 नवंबर, तीसरे चरण को 18 जनवरी और दूसरे चरण को 19 फरवरी को हटाया जा चुका है। केन्द्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। इसमें राजधानी के भीतर चल रहे प्रदूषण के हाल को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि बीते कई दिनों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे है। प्रदूषण की निगरानी करने वाली संस्थाओं का मानना है कि

अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण मध्यम श्रेणी में ही बना रहेगा। इसके बाद ग्रैप के पहले चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया। आयोग ने साथ ही सरकार सहित प्रदूषण को रोकने में जुटी एजेंसियों को आदेश दिया है कि वह इस दिशा में काम करते रहें और प्रदूषण को लेकर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि यह दोबारा न बढ़ जाए। मंगलवार को हवा की रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रतिघंटा रही। अगले कुछ दिनों में यह 8 से 30 किलोमीटर तक रहेगी। राजधानी में अगले चार दिनों तक प्रदूषण से राहत बनी रहेगी। मंगलवार को दिल्ली में हुई हल्की बारिश और हवा की रफ्तार बढ़ने के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी देखने को मिली। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण मध्यम श्रेणी में ही बना हुआ है। सोमवार के मुकाबले वायु गुणवत्ता में मंगलवार को हल्का सुधार देखने को मिला। सोमवार को जहां एक्यूआई 170 दर्ज किया गया था, मंगलवार को यह 159 अंकों पर रहा। जहांगीरपुरी, आनंद विहार, एनएसआईटी द्वारका और शादीपुर में हवा खराब श्रेणी में रही।

फेफड़ों से पानी निकलते समय फंस गई थीं सुईं, सफदरजंग के डॉक्टरों ने बचाई जान

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के एक अस्पताल में फेफड़ों से पानी निकालते समय एक मरीज के फेफड़ों में सुई टूटकर फंस गई। इसके बाद अस्पताल ने मरीज को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। यहां सांस रोग विभाग के डॉक्टरों ने थोरैकोस्कोपी प्रक्रिया के जरिए फेफड़ों से सुई निकालकर मरीज की जान बचाई। सफदरजंग के सांस रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि यह बेहद दुर्लभ मामला है जब किसी चिकित्सीय प्रक्रिया के समय फेफड़ों के प्लयूरल बिंदु में सुई फंस गई हो। उन्होंने बताया कि 45 वर्षीय महिला का एक दूसरे अस्पताल में फेफड़ों का इलाज चल रहा था। यहां मौजूद डॉक्टरों ने उसके फेफड़ों में मौजूद पानी निकालने के लिए प्रयास किया। हालांकि इस दुर्लभ मामले में करीब चार सेंटीमीटर लंबी सुई मरीज के फेफड़ों में टूटकर फंस गई। मरीज को जब हमारे पास भेजा गया था स्कैन किया गया। इसमें पता चला कि एक सुई फंसी हुई है। सफदरजंग के डॉक्टरों की टीम ने थोरैकोस्कोपी प्रक्रिया के जरिए मरीज की छाती में बेहद हलका छेद करके इस सुई को बाहर खींच लिया। मरीज अब ठीक है। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक दुर्लभ मामला है।

समुद्र में कार्बन जमा करवाएगा जर्मनी

बर्लिन, एजेंसी। जर्मन सरकार कुछ उद्योगों को कार्बन कैप्चर कर उसे समुद्र तल के नीचे जमा करने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है. इससे जर्मनी को साल 2045 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.जर्मनी कुछ उद्योगों में कार्बन कैप्चर करने और उसे समुद्र तल के नीचे इकट्ठा करने की तकनीक को अनुमति देने की योजना बना रहा है. जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री रोबर्ट हाबेक ने यह जानकारी दी. कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस), कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक तकनीक है. इसमें पहले तो औद्योगिक गतिविधियों से निकले सीओटू को कैप्चर किया जाता है.

फिर इसे निर्धारित जगह पर ले जाकर जमीन के भीतर इसका भंडारण किया जाता है. स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है. बिजली उत्पादन में कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से भी बड़ी मात्रा में कार्बन निकलता है. ये गतिविधियां ग्लोबल वॉर्मिंग में बड़ी भूमिका निभा रही हैं. जानकार रेखांकित करते हैं कि पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें ना केवल उत्सर्जन घटाने की जरूरत है, बल्कि वातावरण में मौजूद कार्बन को हटाने की तकनीकों पर भी काम करना होगा. जर्मनी की योजना क्या है? हाबेक ने जर्मन सरकार की कार्बन प्रबंधन रणनीति पर एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह तकनीक सुरक्षित है.

जर्मनी साल 2045 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है. वर्तमान में यह सीओटू उत्सजर्न के मामले में यूरोप में सबसे ऊपर है. हाबेक, जर्मनी की जलवायु परिवर्तन नीति के लिए भी जिम्मेदार हैं. उन्होंने बताया कि सीमेंट उत्पादन जैसे कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी. इससे जर्मनी अपने जलवायु लक्ष्यों तक पहुंच सकेगा. हाबेक के मुताबिक, जमीन के ऊपर सीओटू को इकट्ठा करना प्रतिबंधित रहेगा.

2012 में पास हुए एक कानून ने जर्मनी के राज्यों को कार्बन कैप्चर तकनीक के इस्तेमाल पर वीटो लगाने का अधिकार दिया था. अब रोबर्ट हाबेक ने कहा है कि इस कानून में भी बदलाव की जरूरत है।

किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी फॉर्मूले को हर हाल में बदलवाना चाहता है भारत

अबूधाबी एजेंसी।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 (एमसी13) में भारत हर हाल में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के फॉर्मूले में संशोधन चाहता है। अभी वर्ष 85-86 के मूल्य के आधार पर सब्सिडी दी जाती है और इस हिसाब से गेहूं-चावल जैसे अनाज के लिए 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की कीमत पर किसानों से खरीदारी करने पर विकसित देश उसे सब्सिडी मानते हैं।

मतलब अगर किसानों से 30 रुपये प्रति किलोग्राम अनाज सरकार खरीदती है तो विकसित देश मानते हैं कि किसानों को प्रति किलोग्राम 26.80 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और इस आधार पर भारत व अन्य विकासशील देशों के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अधिक दिखती है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है।

विकसित देश पहले से ही विकासशील देशों के मुकाबले अपने किसानों को काफी अधिक सब्सिडी दे रहे हैं। भारत सब्सिडी के इस आधार मूल्य को वर्तमान मूल्य पर तय कराना चाहता है। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक वर्ष 85-86 के मूल्य के आधार पर उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। हालांकि वर्ष 2013 की एमसी

बैठक के पीस क्लॉज की वजह से किसी भी देश की सब्सिडी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। एमसी13 में बुधवार को होने वाली बैठक में भारत व अन्य विकासशील देश पब्लिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) के स्थायी समाधान के मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेगा। मंगलवार को एमसी13 की बैठक में भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने मछुआरों के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने कहा है कि हमारे मछुआरों की तुलना मछली का कारोबार करने वाली विकसित देशों के कॉरपोरेट कंपनियों से नहीं करनी चाहिए। भारत के मछुआरे अपनी जिंदगी जीने के लिए मछली पकड़ने का काम करते हैं, इसलिए मछली पालन पर सब्सिडी को लेकर अगर कोई भी नियम बनता है तो एक समग्र नीति बनाई जानी चाहिए। बैठक में भारत ने साफ किया हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के दौरान पहले से ही पर्यावरण का ख्याल रखते हैं और इस नाम पर उनकी रोजी-रोटी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। मंगलवार को एमसी13 की बैठक में 72 देशों के समूह ने घरेलू सेवा नियामक (एसडीआर) पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश सहमत हो गए। ये 72 देश डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को अपने देश में प्रोफेशनल्स सेवा देने में सहूलियत प्रदान करेंगे और सभी देशों को एक समान सुविधाएं मिलेंगी।

चक माव्हिनी का 74 वर्ष में हुआ निधन, मरीन कॉर्प्स इतिहास में थे सबसे तेज स्नाइपर

वियतनाम एजेंसी। चक मावहनी, जिनकी दक्षिण वियतनाम के घने जंगल और उगती हाथी घास के बीच रेंगने की क्षमता और फिर एक दुश्मन सैनिक को मारने के लिए अपनी स्कोप्ड राइफल के साथ घंटों तक इंतजार करने की क्षमता ने उन्हें मरीन कॉर्प्स के इतिहास में सबसे तेज स्नाइपर बना दिया है। उनकी 12 फरवरी बेकर सिटी में, ओरेगॉन के उत्तरपूर्वी कोने में एक शहर में उनकी मृत्यु हो गई। वह 74 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु की घोषणा बेकर सिटी में कोल्स फ्यूनरल होम द्वारा की गई। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। मई 1968 से मार्च 1970 तक वियतनाम में सेवा करने वाले मावहनी ने 103 हत्याओं की पुष्टि की और अन्य 216 संभावित हत्याएं कीं, औसतन प्रति सप्ताह लगभग चार - औसत कंपनी से अधिक, जिसमें लगभग 150 सैनिक शामिल थे। अमेरिकी सैन्य स्नाइपरों में, केवल क्रिस काइल, एक नेवी सील, जिन्होंने इराक में सेवा की और 160 हत्याओं की पुष्टि की और एडेलबर्ट वाल्ड्रॉन,

वियतनाम युद्ध के दौरान 109 हत्याओं के साथ एक आर्मी स्नाइपर, की संख्या मावहनी से अधिक थी। एक स्नाइपर के रूप में, माव्हिनी ने कई भूमिकाएँ निभाईं। वह पूरी रात अपनी राइफल और नाइट स्कोप के साथ जागते रहते थे और घुसपैठ के लिए किसी छावनी की परिधि पर नजर रखते थे। वह अन्य नौसैनिकों के साथ गश्त पर निकलते थे, और यदि कोई गोलीबारी होती तो उनका सामना करने के लिए तैयार रहते थे।

उनकी अधिकांश हत्याएं धीरे-धीरे हुईं, घंटों के इंतजार के बाद उनके बोल्ट-एक्शन एम40 से एक शॉट निकला। लेकिन 14 फरवरी, 1969 की रात को कुछ विस्फोट हुए। माव्हिनी ने उत्तरी वियतनामी सैनिकों के एक दल को दा नांग के पास एक उथली नदी को पार करते हुए, एक समुद्री छावनी की ओर बढ़ते हुए देखा। उसने गोलीबारी शुरू कर दी और 30 सेकंड में उसने 16 को मार डाला और बाकी पीछे हट गए। माव्हिनी ग्रामीण पूर्वी ओरेगॉन में पले-बढ़े और उन्होंने अपने नाना से निशानेबाजी सीखी। वह हिरणों के शिकार के पक्षधर थे और वह जंगल में कई दिन बिताते थे, वहां डेरा डालते थे और अपने शिकार का तब तक पीछा करते रहते थे जब तक कि उन्हें शिकार न मिल जाए। यह, उनके युद्धकालीन भविष्य के लिए उत्तम प्रशिक्षण था। उन्होंने कहा, उन्हें हत्या करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपने साथी नौसैनिकों को सुरक्षित रखने के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वीकार किया। जब उनके एक कमांडर ने अपने शिविर में एक स्नाइपर लीडरबोर्ड पोस्ट किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी हत्या की संख्या के आधार पर रैंकिंग दी गई, तो मावहनी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह अरुचिकर है और इससे भी बुरी बात यह है कि यह लोगों को प्रतिस्पर्धा के नाम पर घातक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। चार्ल्स बेंजामिन मावहिनी का जन्म 23 फरवरी, 1949 को लेकव्यू, ओरेगन में चार्ल्स और बेउला (फ्रांज) मावहिनी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत थिएटर में लड़ते हुए मरीन में सेवा की थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में मरीन कॉर्प्स इंस्टालेशन, कैंप पेंडलटन में नए स्काउट स्नाइपर स्कूल को पूरा करने वाले पहले लोगों में माव्हिनी शामिल थे। उन्होंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

इमरान की पार्टी ने मरयम को बताया पंजाब की 'फर्जी मुख्यमंत्री, कहा- जनता पर थोपी गई यह कैलिबरी क्वीन

इस्लमाबाद, एजेंसी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने मंगलवार को मरयम नवाज को पंजाब प्रांत की 'फर्जी मुख्यमंत्री करार दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी की 50 वर्षीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम ने सोमवार को पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रवक्ता रऊफ हसन ने एक बयान में कहा कि कैलिबरी क्वीन (मरयम) को आम चुनावों में लोगों के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विडंबना यह है कि उन्हें पंजाब के लोगों पर थोप दिया गया है। हसन ने कहा कि मरयम को फर्जी सदन के फर्जी प्रतिनिधियों के मतों के माध्यम से धोखाधड़ी करके चुना गया है। पीटीआई दावा कर रही है कि मरयम आठ फरवरी के चुनाव में 800 से अधिक मतों के अंतर से अपनी सीट हार गई थीं। हसन ने कहा कि प्रमाणित चोरों का परिवार, जिन्होंने दशकों तक राष्ट्रीय खजाने को खूब लूटा है, वो अब लोगों के वोट चुराने के बाद जनादेश चोर के रूप में याद किए जाएंगे।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक:- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय

कार्यालय पता:- 435 ऑर्बिट मॉल विजय नगर, इंदौर मध्यप्रदेश मो:- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा।

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार, आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।